मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/5256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 05
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 23 अंक : 6

5 फरवरी 2023

चार दशक में बदल गई छिन्दवाड़ा की सूरत और सीरत

मध्यप्रदेश में लागू होना चाहिए छिन्दवाड़ा मॉडल

विजया:)

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 23 अंक 06 05 फरवरी 2023

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
दिल्ली संवाददाता	नीरज दिवाकर
मध्यप्रदेश संवाददाता	अर्चना शर्मा
छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ	मणिशंकर पाण्डेय
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय
बुंदेलखण्ड संवाददाता	रफत खान

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक,

विजया पाठक द्वारा समता ग्राफिक्स
एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. द्वारा कम्पोज एवं जगत प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्लाट नं. 28 सुरभि विहार बीडीए रोड भेल भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.in

चार दशक में बदल गई
छिन्दवाड़ा की
सूरत और सीरत

मध्यप्रदेश में लागू होना चाहिए छिन्दवाड़ा मॉडल

(पृष्ठ क्र.-6)

- भूपेश बघेल का अस्त्र है रासुका 42
- अशोक गहलोत और सचिव पायलट की तल्खी 45
- आम बजट 2023 : गरीब, किसान और ग्राम कल्याण 48
- यूपी की राजनीति में वर्चस्व खोते जा रहे छोटे दल 50
- हिमालय को दिखा रही जल विद्युत परियोजनाएं 52
- चीन को लेकर सावधानी जरूरी 56
- Pollution Control in United States 60

अडानी
हिंडनबर्ग

मिशन 2024 : मोदी बनाम तमाम विपक्ष के बीच मुकाबला

लोकसभा 2024 के रण में भले ही अभी एक साल का समय बचा हो लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए यही लगने लगा है कि यह लड़ाई मोदी बनाम सभी विपक्षियों के बीच प्रारंभ हो गया है। सभी विपक्षी दल अपने आप को मोदी से टक्कर देने के लिए दम भरने लगे हैं। और विपक्षी एकता को कमजोर भी करने लगे हैं। मोदी को हराने के लिए अगर कोई एकीकृत रणनीति नहीं है तो समझ लो 2024 में भाजपा को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। दुनियां के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े त्योहार यानि 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अतिविश्वासी होकर चुनाव लडने को चेताया तो वहीं विपक्ष के अलग अलग मोर्चे अपने अपने विश्वास के दम पर ताल ठोकने लगे हैं। भाजपा को हराने के लिए एकीकृत विपक्ष का होना बेहद आवश्यक है। लेकिन विपक्ष भाजपा को अतिविश्वसी बनने पर मजबूर कर रहा है। जहां एक तरफ़ राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश दिया कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है। वहीं अखिलेश, केसीआर यानि चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल मिलकर सरकार बनाने का सपना बुन रहे हैं। इधर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के खिलाफ इस तरह से जीत पाएगा विपक्ष? जो कि असली विपक्ष है ही नहीं। विपक्ष के जितने मोर्चे बनेंगे उससे भाजपा को कम और भाजपा के विरोधी दलों को यादा नुकसान होगा। इधर लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सभी पार्टियों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। चंद्रशेखर राव 2024 के सिंहासन के सपने देख रहे हैं, लेकिन तेलांगना के विधानसभा चुनाव उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तेलंगाना में जीत नहीं मिली तो किस मुंह से देश का नेतृत्व मांगेंगे? ऐसा ही हाल कांग्रेस का भी है, कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचाना बेहद ज़रूरी हो जाता है, तब जब विपक्ष का भरोसा कांग्रेस से उठने की कगार पर हो। नीतीश कुमार इस जुगलबंदी में हैं कि किसी तरह विपक्ष एक हो जाए और भाजपा को हटाया जाए। लेकिन यहां भी नीतीश ने कुर्सी को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की है। कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर राव ने विपक्ष की एक बड़ी रैली की जिसमें अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और डी राजा शामिल हुए। अखिलेश ने कहा कि जो प्रोग्रेसिव सोच रखता है, ऐसा विपक्ष साथ आ रहा है, तो क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी प्रोग्रेसिव सोच नहीं रखते? राहुल गांधी ने भी इशारों ही इशारों में कह दिया कि कांग्रेस ही असली विपक्ष है। समाजवादी पार्टी के संदर्भ में राहुल पहले ही कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, यह राष्ट्रीय पार्टी जैसे केंद्र में नहीं रह सकती। ऐसे में राहुल का यह संदेश सभी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए हो गया। कुल मिलाकर विपक्ष के कई मोर्चे हो चुके हैं, अगर यह साथ नहीं आते हैं तो 2024 के लिए बात बनना मुश्किल होगी। वहीं भाजपा को अपना लक्ष्य पता है, उसकी तैयारियां उसके अनुरूप हैं।

विजया पाठक

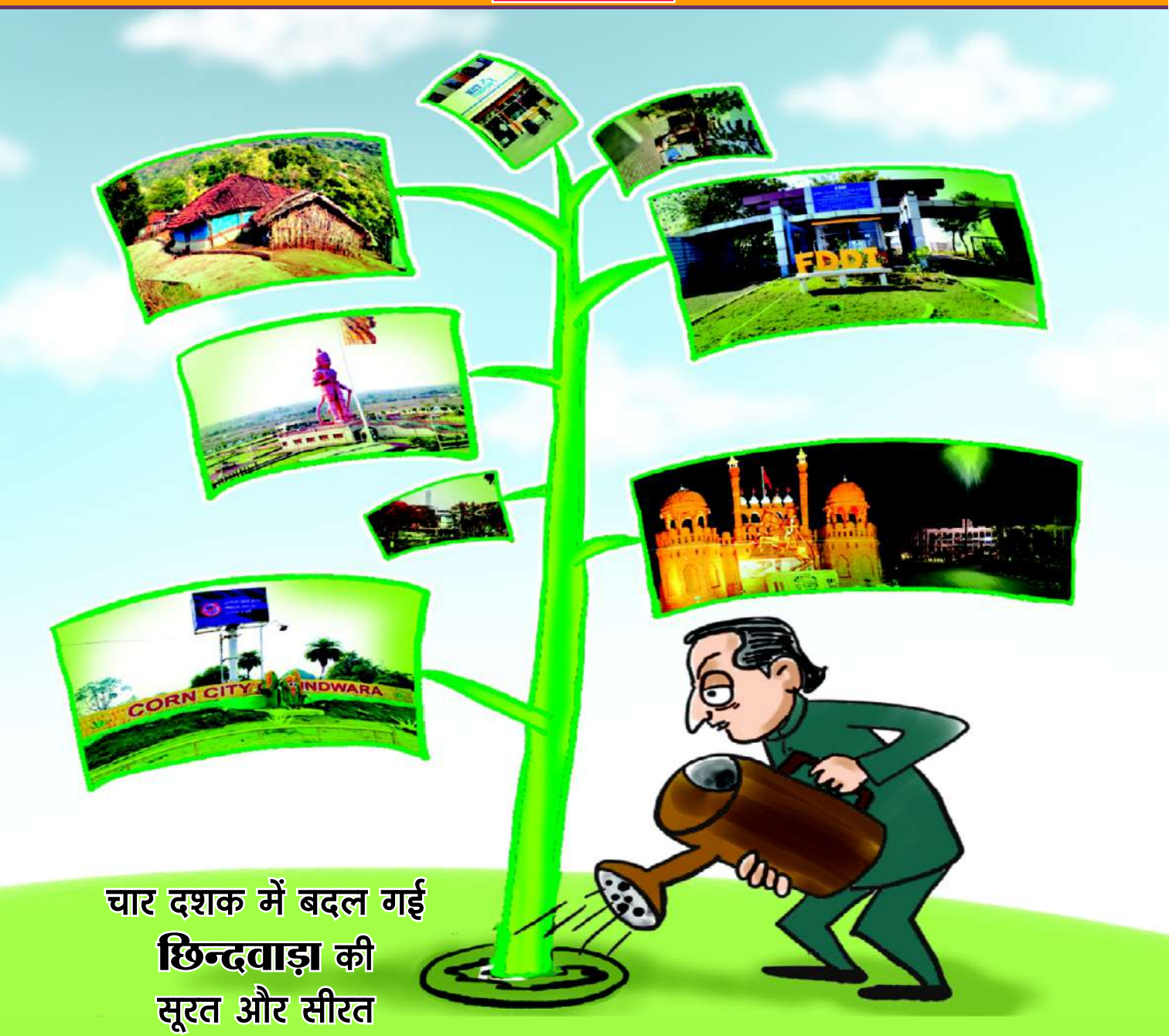

चार दशक में बदल गई
छिन्दवाड़ा की
सूरत और सीरत

मध्यप्रदेश में लागू होना चाहिए छिन्दवाड़ा मॉडल

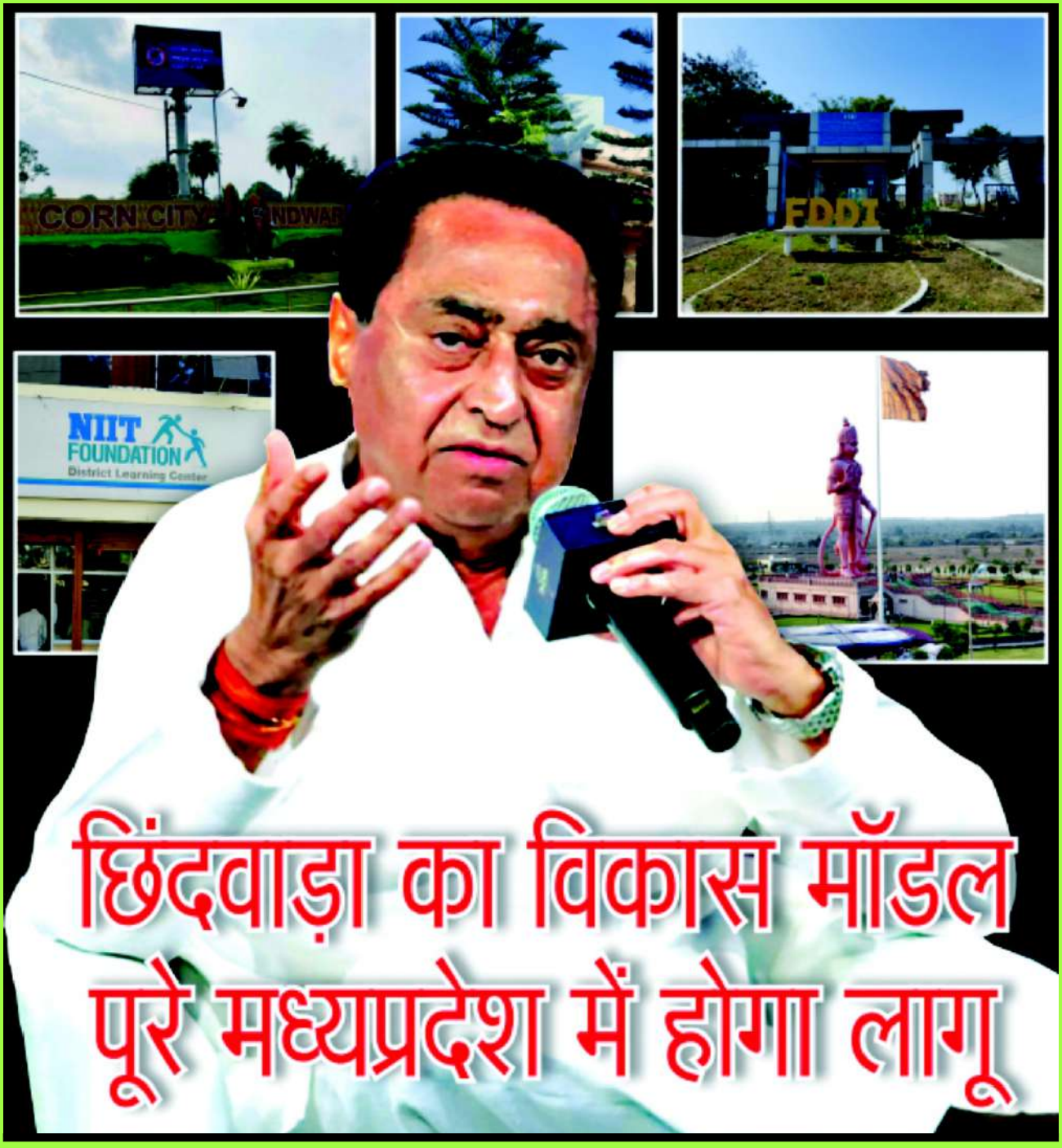

छिंदवाड़ा का विकास मॉडल पूरे मध्यप्रदेश में होगा लागू

हमने ऐसा सिर्फ़ सुना भर था कि जिन्हें मंज़िलों की चाह होती है वो सफ़र के बारे में परवाह नहीं करते। यह बात देखने को मिलती है मध्यप्रदेश में स्थित छिन्दवाड़ा ज़िले में। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के 52 ज़िलों में समृद्धि और विकास में 5वें नंबर पर आता है। ज़िले की अनुमानित जी.डी.पी विगत वर्षो में 22,532 करोड़ रुपये रही है। यहीं नहीं साक्षरता और शिक्षा के क्षेत्र में भी ज़िले का प्रदेश में 19वां स्थान है। इन दो बातों ने इस बात पर ध्यान खींचा कि शिक्षा और संपन्नता में अग्रणी इस ज़िले ने ऐसा क्या कमाल किया है, जो आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर हम छिंदवाड़ा को स्किल कैपिटल ऑफ़ मध्यप्रदेश कहे तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस कमज़ोर नब्ज़ को अभी तक हम टटोल रहे थे छिन्दवाड़ा में वो नब्ज़ ना केवल पकड़ी गई बल्कि बीमारी का इलाज भी शुरू कर दिया गया। वो बीमारी थी युवाओं में बेरोज़गारी, जिसे तुरंत, स्थिर और मज़बूत इलाज की ज़रूरत थी और वो मिला कौशल उन्नयन के माध्यम से। छिन्दवाड़ा में उन्नत किस्म के स्किल सेंटर्स ने आसपास के आदिवासी अंचल के युवाओं के हुनर को समझा और उसे संवारा और उन्हें रोज़गारमूलक प्रशिक्षण देकर उनके जीवन को एक बेहतर दिशा दी। अब हमारे प्रदेश में जिस शिक्षा की जरूरत है वह पारंपरिक शिक्षा नही है। स्किल डेवलपमेंट युवाओं का होना चाहिए। मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा के स्किल डेवलपमेंट स्टेचिनिंग मॉडल को अपनाने की जरुरत है। जब आप अपने शहर में उन युवाओं को मौका देंगे जिनका एक्सपोजर उच्चवर्गीय, मध्यमवर्गीय लोगों से कम होता है तो वह युवा भटकाव की तरफ कम जायेंगे। इन युवाओं को कौशल विकास (स्किल डेवलपमेंट) से जोड़कर हुनरमंद करके अपने ही माहौल में बसाने की जरुरत है। प्रदेश में मशरूम जैसे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय खोल दिए गये हैं, जिनकी शिक्षा युवाओं में रोजगार देने के लायक नही है, उस शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरुरत

स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स से हुनरवान हो रहे छिन्दवाड़ा के लाखों युवा

विजया पाठक

विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में राजनीति का विशेष महत्व है। देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग राजनीति के पेशे में है। कहने को तो राजनीति का प्रमुख कार्य समाजसेवा से है, देशसेवा से है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इस पेशे से जुड़े राजनीतिज्ञ अपने प्रमुख कार्य में अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर रहे हैं। आज देश का प्रत्येक नागरिक इस सवाल पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। यही कारण है कि अब धीरे-धीरे लोगों के बीच राजनीतिज्ञ अपनी गरिमा को खोते जा रहे हैं। कारण भी स्पष्ट हैं कि राजनीतिज्ञ अब इस पेशे को समाजसेवा और देशसेवा को छोड़ व्यवसाय के रूप में उपयोग करने लगे हैं। यही वह कारण है कि राजनेताओं को हीन भावना से देखा जाने लगा है।

है। जब युवकों को शिक्षा और रोज़गार अपने ही शहर में प्रदान की जाएगी, तब ही युवाओं का पलायन एवं भटकाव रूकेगा। उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आयेगा। जब हमारे गांव या छोटे शहर का युवा जीवन में कुछ करने के सपने लिये बड़े शहरों की तरफ रूख करता है तो वहां के तौर-तरीकों में गुम हो जाता है। चूंकि उनके पास अनुभव का अभाव होता है। इसीलिए उनका बड़े शहरों में ठहरना मुश्किल हो जाता है। फिर यही युवा चोरी, चकारी और नशे में डूब जाते हैं। सफल न होने के बाद जब वह अपने गांव लौटता है तो वह इतना हताश हो जाता है कि या तो वह अपना जीवन खत्म कर लेता है या अंधेरे के गर्त में डूब जाता है। छिन्दवाड़ा का कौशल विकास उन्नयन मॉडल हमारे देश के युवाओं में बढ़ते हुए मानसिक अवसाद और आत्महत्या जैसे मामले को रोकने में भी कारगर हो रहा है। छिन्दवाड़ा को रोल मॉडल बनाने के पीछे एक व्यक्ति की सोच ने काम किया है। वह सोच राजनीति और दलगत पार्टियों से उपर है। और यह नाम है कमलनाथ। छिन्दवाड़ा में कौशल विकास उन्नयन के रोजगारमूलक सेन्टर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं। उन्होंने छिन्दवाड़ा के आसपास में 100 किलोमीटर जिसमें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी आता है, वहां युवाओं को रोजगार के मामलों में अपने व्यक्तिगत प्रयास एवं पहचान और मित्रता से छिन्दवाड़ा शहर में युवाओं के लिये रोजगार की अलख जगा दी है। अगर मन में लक्ष्य की चाह हो तो तस्वीर बदली जा सकती है। एक तरफ भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में इन्दौर नम्बर 1 है वहीं छिन्दवाड़ा स्किल डवलपमेंट के मामले में नम्बर 1 है। जहां से स्किल पाकर युवा देश भर की नामी कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह के स्किल सेंटर्स देश के अन्य शहरों में भी स्थापित किये जाने चाहिए। ताकि अधिक से अधिक युवा प्रशिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सकें।

एक लक्ष्य और एक दूरगामी सोच ने बदल दी छिन्दवाड़ा की तस्वीर

लेकिन अपवाद के रूप में देश के अंदर कुछ ऐसे राजनेता भी हैं, जो राजनीति के प्रमुख ध्येय को बरकरार रखे हुए हैं और जनकल्याण में अपने आपको समर्पित किये हुए हैं। ऐसे ही एक राजनेता हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। कमलनाथ ने अपने राजनीतिक जीवन में अपने कार्यो से ऐसी छाप छोड़ी है कि अन्य नेता कमलनाथ के सामने बौने साबित हो रहे हैं। वैसे तो देश के विकास में अनेक कार्यो की प्रशंसा होती है, लेकिन वाकई में उनकी सोच और लक्ष्यों को देखना है तो संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में देखा जा सकता है। छिंदवाड़ा का विकास मॉडल पूरे विश्व में चर्चित है। उन्होंने छिंदवाड़ा के चहुँओर विकास के साथ-साथ समाजसेवा के भी अनुकरणीय कार्य किये हैं। नौजवानों को रोजगार से

जोड़ा है। सीएसआर (उद्योग से प्राप्त आय की 02 प्रतिशत राशि समाज कल्याण के लिए खर्च करना) के माध्यम से छिंदवाड़ा क्षेत्र में शिक्षा, रोज़गार, व्यवसाय के लिए कई संस्थान खुलवाये। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलवाये हैं। स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स स्थापित करवाये हैं। जिनसे प्रत्येक साल हजारों की संख्या में नवयुवक और नवयुवतियां रोजगार हासिल करने में कामयाब हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब गतिविधियां बिल्कुल निःशुल्क हैं और रहने खाने की व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। यही कारण है कि आज छिंदवाड़ा को कमलनाथ का छिंदवाड़ा कहा जाता है। निश्चित ही कमलनाथ ने यह सम्मान और उपाधि क्षणिक भर में नही पायी है बल्कि इसके पीछे उनकी वर्षो की मेहनत, समाज के प्रति उनकी सोच और दूरदृष्टि लक्ष्य हैं, जो आज उनके काम धरातल पर उतर कर अपने आपको प्रदर्शित कर रहे हैं।

निश्चित रूप से आज देश का हर एक राजनीतिज्ञ कमलनाथ जैसी सोच लेकर चले और लोगों के कल्याण के लिए समर्पित हो जाये तो राजनीति का स्तर शिखर पर स्थापित हो जायेगा। छिंदवाड़ा का विकास मॉडल मैंने ग्राउण्ड जीरों पर जाकर देखा है। जगत विज़न की एक टीम के साथ हमने विकास के इस विशेष मॉडल को बारीकी से देखा है। छिंदवाड़ा शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर है। कमलनाथ ने उद्योगपतियों से बेहतर संबंधों का लाभ स्वयं के लिये नहीं लिया बल्कि लोगों के कल्याण के लिए लिया। निश्चित तौर पर आज देश को कमलनाथ जैसी सोच रखने वाले नेताओं की जरुरत है। जो युवाओं के भविष्य की चिंता करता है। हम जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश हैं जिसमें 40 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। युवा ही देश का भविष्य हैं। इनका भविष्य

छिन्दवाड़ा की राजनीति में नये युग का आगाज

छिंदवाड़ा जिले की राजनीति में स्वतंत्रता के बाद दो युग माने जाते हैं। एक वर्तमान युग जो 1980 से निरंतर चल रहा है तथा दूसरा 1952 से 1980 तक का माना जाता है। दोनों युगों के बीच राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से जबरदस्त अंतर परिलक्षित होता है। 1980 से पूर्व सांसद व विधायक क्रमशः लोकसभा व विधानसभा में अपने-अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मात्र करते थे। लेकिन विकास के नाम पर किसी ने भी कोई ठोस पहल नहीं की। जबकि 1980 के बाद छिंदवाड़ा जिले के चुनाव भी विकास पर आधारित होने लगे। 1980 के बाद के जिले के राजनीतिक युग को कमलनाथ युग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस काल में छिंदवाड़ा जिले की राजनीति में अग्रणी व निर्णायक भूमिका में कमलनाथ को ही देखा जा सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि छिंदवाड़ा जिले में नये राजनीतिक युग की शुरुआत कैसे हुई। देश में शायद ही कोई ऐसा स्थान होगा जहां छिंदवाड़ा के समान राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख मिल सकता हो। राजनीति के क्षेत्र में कई प्रकार की घटनाएं इतिहास में उल्लेखनीय हो जाती हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की राजनीति की घटना अन्य घटनाओं से भिन्न है। 1979-80 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ को छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं विधायकों की मांग पर क्षेत्र के पिछड़ेपन को आधार बनाकर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा छिंदवाड़ा भेजा गया। श्रीमती गांधी ने छिंदवाड़ा में चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए कहा मैं अपने तीसरे पुत्र कमलनाथ को आपको सौंप रही हूं। इसे पकड़कर रखना व अपने जिले का विकास करा लेना। आज भी लोगों के जुबान पर श्रीमती गांधी के वे शब्द आ ही जाते हैं। इससे पूर्व भी दिल्ली में जनता पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का नेतृत्व करने के कारण बड़े जोर-शोर से युवा कांग्रेसियों द्वारा यह नारा लगाया जाता था कि इंदिरा गांधी के दो हाथ, संजय गांधी कमलनाथ इन दोनों बातों से कमलनाथ से जुड़े लोग उनके कद का आंकलन प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे हैं। जिस तरह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को तीसरा बेटा बताकर जन-समुदाय के सामने यह कह दिया कि इन्हें पकड़कर रखना, ये करेंगे छिंदवाड़ा का विकास। यह बिल्कुल साधारण बात नहीं थी। श्रीमती इंदिरा गांधी को देश की जनता बहुत अधिक चाहती थी। उन्हें मां के रुप में मानने वालों की कमी नहीं थी।

उज्जवल करना हमारे देश के नीति निर्धारकों का कर्तव्य है। इससे न केवल युवाओं का विकास होगा। बल्कि देश का भी विकास होगा। कमलनाथ को करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि उनमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो ललक है वह निरंतर जारी है। जब भी युवाओं को लेकर कोई अवसर आता है वह उसे साकार करने में लग जाते हैं। वह सत्ता

राष्ट्रीय स्तर पर अनुकरणीय है छिन्दवाड़ा के स्किल डेवलपमेंट का मॉडल

विश्व के विकसित राष्ट्रों में स्किल डेवलपमेंट हेतु संचालित कार्यक्रम वहां उपलब्ध संसाधनों एवं औद्योगिक वातावरण के अनुरूप है। भारतीय परिपेक्ष्य में भी इस दिशा में किये गये प्रयासों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 1945 से ही स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं। शासकीय स्तर पर भी कई सार्वजनिक संस्थानों द्वारा स्कूल एजुकेशन के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी प्रयास किये जाते रहे हैं। भारत शासन ने 2008-09 के बजट में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कर्पोरेशन का गठन कर देश भर में स्किल्स डेवलपमेंट के कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने का निर्णय लेते हुए वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए। उसके पश्चात् एन.एस.डी.सी. से अनुदान प्राप्त कर देश भर के कोनों में स्किल डेवलपमेंट के अंशकालिक प्रोग्राम संचालित किये जाने लगे। देश के विभिन्न राज्यों में राज्य शासन द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास छिंदवाड़ा में किये गये वह परिणिति को प्राप्त कर मील का पत्थर साबित हुआ।

स्किल डेवलपमेंट के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयासों की शुरुआत विश्व के कुछ विकसित देशों में संभवतः काफी पहले से ही हो चुकी थी। लेकिन विश्व के विकसित राष्ट्रों में स्किल डेवलपमेंट हेतु संचालित कार्यक्रम वहां उपलब्ध संसाधनों एवं औद्योगिक वातावरण के अनुरूप है। भारतीय परिपेक्ष्य में भी इस दिशा में किये गये प्रयासों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 1945 से ही स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रयास किये जाते रहे हैं। शासकीय स्तर पर भी कई सार्वजनिक संस्थानों द्वारा स्कूल एजुकेशन के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट की दिशा में भी प्रयास किये जाते रहे हैं। भारत शासन ने 2008-09 के बजट में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कर्पोरेशन का गठन कर देश भर में स्किल्स डेवलपमेंट के कार्यक्रम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने का निर्णय लेते हुए वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किए। उसके पश्चात् एन.एस.डी.सी. से अनुदान प्राप्त कर देश भर के कोनों में स्किल डेवलपमेंट के अंशकालिक प्रोग्राम संचालित किये जाने लगे। देश के विभिन्न राज्यों में राज्य शासन द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम संचालित किये जा रहे हैं। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास छिंदवाड़ा में किये गये वह परिणिति को प्राप्त कर मील का पत्थर साबित हुआ। कम्प्यूटर क्रांति के साथ ही छिंदवाड़ा जिले में अधिकांश स्कूलों में कम्प्यूटर एजुकेशन प्रदान करने के लिए कम्प्यूटर प्रदान किये गये। जिले में कम्प्यूटर एजुकेशन सेंटर्स संचालित करने वालों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रोत्साहित किया। डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स के पास आऊट

में रहे हो या सत्ता से बाहर रहे हो उन्होंने अपने लक्ष्यों को कभी भी कमजोर नही होने दिया। यही कारण है कि 1980 से आज तक वह छिंदवाड़ा से अजेय हैं। लोगों का नजरिया उनके प्रति एक अभिभावक के रूप में है।

छात्रों को वे देश प्रदेश की नामी कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने के निरंतर प्रयास होते रहे। इसी कड़ी में कमलनाथ द्वारा छिंदवाड़ा के कम्प्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से कम्प्यूटर शिक्षा में सर्टिफिकेट कोर्स के पास आउट छात्रों में से 100 छात्रों के आवेदन मंगाये गये। उन सभी आवेदनों को देखने के बाद कमलनाथ ने विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी से चर्चा कर उनके द्वारा अधिकृत कंपनी के अधिकारी के पास भेज दिया। विप्रो के अधिकारियों ने सभी आवेदनों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वे उनकी कम्पनी में काम करने लायक योग्यता नहीं रखते। यह बात कमलनाथ को अत्यंत पीड़ादायक लगी। उन्होंने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से ले लिया तथा वे देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपतियों द्वारा संचालित उद्योगों में काम करने लायक युवाओं की योग्यता के बारे में जानकारी लेने में जुट गये। उन्होंने उसी समय यह दृढ़ संकल्प लिया कि अपने क्षेत्र के युवाओं को वे उस लायक बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि कोई भी कंपनी या उद्योग उन्हें अयोग्य करार न दे सके तथा जहां भी वे जाएं उन्हें अपनी योग्यता के अनुरुप काम करने का अवसर अवश्य मिले। कमलनाथ ने एन.आई.आई.टी. फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेन्द्र पवार को चर्चा हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने श्री पवार से आग्रह किया कि वे छिंदवाड़ा में कम्प्यूटर में काम करने लायक स्किल डेवलप करने के लिए सेंटर स्थापित करें। इस पर श्री पवार ने उन्हें जवाब दिया कि वे केवल फ्रेन्चाइसी ही दे सकते हैं। फ्रेन्चाइसी को उद्योगों में कार्य करने लायक स्किल डेवलप करने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने पीपीपी मॉडल पर छिंदवाड़ा में एनआईआईटी का सेन्टर खोलने का निर्णय ले लिया। कमलनाथ स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में केवल कम्प्यूटर ट्रेनिंग तक ही सीमित रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो देश भर के नामी उद्योगों से काम करने लायक स्किल की आवश्यकता की सूची बना रखी थी। वे यह भली-भाँति जानते थे कि इंजीनियरिंग की डिग्री व उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को तो नामी कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त हो जाता है लेकिन 5वीं, 8वीं, 10वीं व 12वीं पास युवा जो किन्ही कारणों से आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते, को उद्योगों में तकनीकी काम करने का मौका नहीं मिलता। वे वहां केवल लेबर बनकर रह जाते हैं। इसलिए उन्हें उद्योगों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने संबंधित ट्रेनिंग देकर ऑपरेटर स्तर का जॉब दिलाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के पदाधिकारियों से चर्चा की तथा स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के लिए सीआईआई द्वारा नॉलेज सेंटर छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया। नॉलेज सेंटर्स में ट्रेनिंग संबंधी पाठ्यक्रम शुरु करने के लिए सर्वप्रथम

अगर छिंदवाड़ा क्षेत्र के अधोसंरचना विकास की बात की जाये तो आज का छिंदवाड़ा अन्य दूसरे क्षेत्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में है। यह क्षेत्र रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, कृषि जैसी बुनियादी क्षेत्रों में विकसित

जिले में कौशल विकास के 10 केन्द्र संचालित हैं

आतिश ठाकरे, जिला स्किल डेव्लेपमेंट को-ऑर्डिनेटर, छिंदवाड़ा

आतिश ठाकरे से जगत विजन की संपादक विजया पाठक की चर्चा

छिन्दवाड़ा जिले में 2007 से कौशल विकास और रोज़गार की यात्रा लगातार जारी है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का हमेशा से लक्ष्य रहा है कि छिंदवाड़ा के युवाओं को शिक्षा, रोज़गार कौशल विकास के मौके लगातार मिलते रहे। इनकी प्राथमिकता में हमेशा युवा रहते हैं। छिंदवाड़ा जिले में कौशल विकास के 10 केन्द्र संचालित हैं, जिनमें प्रत्येक साल हजारों बच्चे रोज़गार पा रहे हैं। उद्योगपतियों से कमलनाथ जी के व्यक्तिगत संबंधों का फायदा सिर्फ छिन्दवाड़ा का मिला है। कमलनाथ जी के प्रयासों से यह सेंटर चल रहे हैं। इन सेंटर्स के माध्यम से अभी तक लगभग 80 हजार बच्चों को रोज़गार और स्व-रोज़गार से जोड़ा जा चुका है। इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का सहयोग नहीं लिया गया है। यह सभी सेंटर नि-शुल्क ट्रेनिंग देते हैं और सीएसआर के माध्यम से पूर खर्च वहन किया जाता है। इसके अलावा कमलनाथ जी की सोच रही है कि छिंदवाड़ा विकास का मॉडल बने। जिसमें रोड, रेल्वे, कृषि, हार्टीकल्चर जैसे क्षेत्र भी समाहित हैं। छिंदवाड़ा का विकास लगातार जारी है लेकिन प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार जाने से विकास का काम धीमा हुआ है। वर्तमान सरकार ने स्वीकृत बजट रोक दिया है। कमलनाथ जी ने 25 हजार करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये थे। गारमेंट्स पार्क, मल्टी-सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, कन्हान सिंचाई परियोजना, काम्पलेक्स, पॉवर प्लांट, एयरपोर्ट और बहुत सारे कार्य स्वीकृत हुए थे। अब शिवराज सरकार ने इनमें से कई कार्यो की गति धीमी कर दी है और कई को रद्द कर दिया है। ये सरकार भेद-भाव कर रही है।

एल.एंड.टी. कंपनी ने अपनी फैकल्टी को ट्रेन से छिंदवाड़ा भेजा। एल.एंड.टी. कंपनी की फैकल्टी ने सर्वप्रथम छिंदवाड़ा में हैवी ड्यूटी मशीनों के आपरेशन की ट्रेनिंग युवाओं को प्रदान करने का पाठ्यक्रम शुरु किया। देश के नामी औद्योगिक घरानों ने यह माना कि उद्योगों में काम करने लायक स्किल्स तैयार करने हेतु स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित करने से उद्योगों को स्किल की कमी से

है। 1980 (जब से कमलनाथ छिंदवाड़ा के सांसद बने हैं) का छिंदवाड़ा और आज के छिंदवाड़ा में जमीन आसमान का फर्क है। 1980 से विकास का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वह आज भी निरंतर जारी है। इन 42 वर्षो में छिंदवाड़ा का कायापलट हो गया है।

होने वाले नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा परफेक्ट टेक्निकल हैंड्स मिलने से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। इस प्रकार स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को 2009 में ही एक मॉडल के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी थी। छिंदवाड़ा जिले में देश के नामी औद्योगिक समूहों द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट सेन्टर्स से अंशकालिक पाठ्यक्रम के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त शत-प्रतिशत युवाओं को उद्योगों में काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां छिंदवाड़ा के समान प्रायोगिक धरातल पर परफेक्ट स्किल डेवलपमेंट सेन्टर्स संचालित किये जा रहे हो।

काल सेन्टर्स तथा टाटा काल सेन्टर की स्थापना क्रमशः छिंदवाड़ा, सौंसर, चांद व अम्बाड़ा (परासिया) में की है। जिसके कारण जिले में युवाओं के मन में जबरदस्त आत्मनिर्भरता के भाव पैदा हुए हैं तथा अधिकांश युवा नियमित प्रवृति के जॉब को पाने हेतु योग्यता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

एन.आई.आई.टी: युवा बन रहे आत्मनिर्भर

निश्चित रूप से छिंदवाड़ा सम्पूर्ण देश के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु प्रादर्श प्रस्तुत करता है। एन.आई.आई.टी. व अंबुजा फाउंडेशन द्वारा संचालित स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स से काल सेंटर आपरेटर्स की ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं के लिए जिले में ही रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराते हुए एजिस काल सेन्टर, रूरल सोर्स

जिले में स्किल्स डेवलपमेंट के लिए पहले संस्थान के रुप में एन.आई.आई.टी का सेंटर 2007 में स्थापित किया गया। संभवतः देश के इतिहास में पहली बार देश के कम्प्यूटर क्षेत्र के नामी उद्योगों के वरिष्ठतम पदाधिकारियों की उपस्थिति में कम्प्यूटर स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया गया। एन.आई.आई.टी.

आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में विकास शून्य से शिखर तक जा पहुंचा है। वाकई में छिदवाड़ा के विकास मॉडल ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है। जिससे देश के सारे राजनेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या की

छिंदवाड़ा सेन्टर के सन् 2007 में उद्घाटन अवसर पर 12 नामी कंपनियों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया ताकि संबंधित कंपनियां अपनी आवश्यकता के अनुरूप स्किल डेवपलमेंट हेतु संस्थान को मार्गदर्शन दे सके। जिन कंपनियों के पदाधिकारियों ने एनआईआईटी छिंदवाड़ा के उद्घाटन समारोह में भागीदारी निभाई उनमें विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस, डेल, सुजलान, आईबीएम आदि प्रमुख हैं। एनआईआईटी छिंदवाड़ा में साफ्टवेयर ऑपरेटिंग, प्रोफेशनल लाइफ स्किल्स, रिटेल, हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग संबंधित अंशकालिक कोर्सेस संचालित किये जा रहे हैं। संबंधित कोर्स में तीन माह से लेकर तीन साल तक के सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्सेस शामिल हैं। इस संस्थान द्वारा औद्योगिक समूहों में सर्वाधिक मांग से युक्त तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम एडवांस डिप्लोमा इन इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। संस्थान के सेन्टर हेड का कहना है कि 300 से 350 बच्चों की बेच निरंतर चलती रहती है। विभिन्न कोर्सेस के पास-आउट 70 प्रतिशत छात्रों को संबंधित कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त हो जाता है। जबकि शेष 30 प्रतिशत स्वयं का कारोबार स्थापित कर लेते हैं। छिंदवाड़ा जिले के ही बड़कुही नामक ग्राम में एनआईआईटी द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित किया जा रहा है।

अब तक 50 हजार बच्चों का प्लेसमेंट किया जा चुका है

विजय कुसुम्बे, एनआईआईटी फाउंडेशन, छिंदवाड़ा

2007 में छिंदवाड़ा में पहला इंस्टीट्यूट खुला था। अब जिले में और भी कई ऐसे ही इंस्टीट्यूट हैं। इन इंस्टीट्यूट से अब तक 50 हजार बच्चों को प्लेसमेंट दिया जा चुका है। हम लोग नामीनल फीस लेकर बच्चों का दाखिला कराते हैं। जरुरतमंदों को सेवा देते हैं। यह पूरी तरह स्किल बेस ट्रेनिंग है। आदिवासियों को प्राथमिकता देते हैं। 25 प्रतिशत आदिवासी बच्चों को दाखिला देते हैं। यह सभी इंस्टीट्यूट कमलनाथ जी के प्रयास और प्रेरणा से संचालित हो रहे हैं। उद्योगपतियों से कमलनाथ जी के बेहतर संबंधों के कारण इंस्टीट्यूटों का संचालन हो रहा है और बच्चों को रोज़गार मिल रहा है। कमलनाथ जी स्वयं उद्योगपतियों से कहते हैं कि पहले हमारे

इंस्टीट्यूटों का सर्वे करें। यदि काबिल बच्चों हो तो अपनी कंपनियों में दाखिल करें। कमलनाथ जी केम्पस सिलेक्शन कराते हैं। छिंदवाड़ा के बच्चों का आफ कैम्पस कराते हैं। कमलनाथ जी एक विजन लेकर चलते हैं। उनका विज़न दूरदृष्टा होता है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नही है। इन इंस्टीट्यूट के बारे में वे स्वयं जानकारियां लेते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में 500 लोग काम करते हैं। कमलनाथ जी ने इन इंस्टीट्यूट के बारे में 15 साल पहले ही सोच लिया था, जिसकी आज कितनी आवश्यकता है, हम सब जानते हैं। निश्चित ही उनकी सोच दूरदृष्टा है।

सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर : विभिन्न विधाओं से पारंगत हो रहे युवा

सीआईआई के सदस्य औद्योगिक घरानों ने प्रस्तावित स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाने में रूचि दिखाई

ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस विशाल जनसंख्या को संभालने और उनका जीवन यापन बेहतर तरीके से हो, इसके लिए हमारे नेताओं को बहुत कुछ करने और सोचने की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए

है। 2009 में ही चार प्रतिष्ठित कंपनियों ने सीआईआई द्वारा छिंदवाड़ा में स्थापित सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग पाठ्यक्रमों की शुरुआत कर दी थी। उस समय यह सेंटर डब्ल्यूसीएल के भवन में संचालित था। सेंटर के संचालन हेतु छिंदवाड़ा नगर के इमलीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई। जहां आठ ट्रेनिंग रुम, एक कांफ्रेंस रुम, एक मेडिकल रुम, एक कॉमन स्टाफ रूम, तीन ऑफिस स्पेस, एक स्टोर रुम, एक मल्टीपरपस रुम, डायनिंग हॉल (100 स्टूडेंट के लिए), होटल, डारमेट्री, होस्टल आदि की सुविधा उपलब्ध है। उक्त सेंटर में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले छात्रों से छात्रावास की फीस नहीं ली जाती। प्रत्येक कोर्स के लिए छात्रों से नाम मात्र की फीस लेने की व्यवस्था की गई है। ट्रेनिंग प्राप्त करने योग्य छात्रों व युवाओं का चयन करने के लिए सीआईआई ने एक मार्केटिंग टीम भी गठित की है। सेंटर में कमिंस जनरेटर टेक्नोलॉजी लि. द्वारा लो हार्स पावर, जेनटेक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दो माह का कोर्स डीलर पाइंट पर शत-प्रतिशत प्लेसमेंट की गारंटी के साथ संचालित किया जा रहा है। जिसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य है। जीएमआर वारालक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा माइक्रो एरीगेशन एवं प्लंबिंग का तीन माह का कोर्स संचालित है। जिसके लिए 10वीं पास अनिवार्य योग्यता है। यह कंपनी शत-प्रतिशत ट्रेड स्किल्स को जॉब अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराती है। जेनको लिमिटेड द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन मशीन मेंटेनेंस का दो माह का कोर्स फिटर, वेल्डर, टर्नर व इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई डिप्लोमाधारी युवाओं के लिए संचालित है। यह कंपनी प्रत्येक बैच के टॉप 05 ट्रेनर को जॉब प्रदान करती है। शेष ट्रेनर्स को भी अन्य कंपनियों में जॉब आसानी से मिल जाता है। जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा 8वीं पास

निश्चित रुप से छिंदवाड़ा मॉडल को विजन डाक्युमेंट के रुप में जन स्वीकार्यता मिल सकती है क्योंकि 1980 से पूर्व के अत्यंत पिछड़े, दुर्गम एवं अनुत्पादक छिंदवाड़ा जिले को देखने व जानने वाले इस समय हमारे बीच मौजूद हैं। उम्र के चौथे पड़ाव पर

ड्राइविंग लाइसेंसधारी युवाओं के लिए एक माह का ट्रेनिंग कोर्स बैक होल्ड लोडर आपरेटर हेतु चलाया जा रहा है। आपरेटर्स की जितनी डिमांड है उसकी तुलना में 10 प्रतिशत भी प्रशिक्षित युवक नहीं मिल पा रहे हैं। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा तीन-तीन माह के बार वेल्डिंग एवं मेशनरी के ट्रेनिंग कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। उक्त कंपनी शत-प्रतिशत ट्रेनर्स को अपने कंस्ट्रक्शन साइट में जॉब दे देती है। महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा 10वीं पास युवाओं को ट्रेक्टर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की एक माह की ट्रेनिंग दी जा रही है। उक्त कंपनी भी डीलर पाइंट पर शत-प्रतिशत ट्रेनर्स को जॉब दिला देती है। शापुजी पाहुंजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा 12वीं पास युवाओं के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर का चार माह का कोर्स संचालित किया जा रहा है। उक्त कंपनी 40 प्रतिशत ट्रेनर्स को अपने ही निर्माण साइट्स में जॉब उपलब्ध करा देते हैं। टाटा किलोस्कर मोटर प्रा. लि. द्वारा टोस्टा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग प्रोग्राम का तीन माह का कोर्स जिसके लिए डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक एवं ऑटो मोबाइल में आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य है। कंपनी भी शत-प्रतिशत ट्रेनर्स को डीलर पाइंट पर जॉब दिला देती है। इसके अलावा ताज होटल रिसोर्ट एंड पैलेस द्वारा 10वीं पास युवाओं के लिए तीन-तीन माह के कोर्स इंडियन कुकिंग एवं कनफेशनरी बेकिंग के कोर्स शत-प्रतिशत जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ शुरु किये जा रहे हैं। सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर हेड अमित दुबे के अनुसार पॉलिटेक्निक डिप्लोमा व इंजीनियरिंग की डिग्रीधारी युवाओं के लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेस शुरु करने के लिए सीआईआई के वरिष्ठतम पदाधिकारी निरंतर प्रयासरत हैं। इस सेंटर में स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स संचालित करने हेतु सीआईआई के अन्य सदस्य औद्योगिक समूह भी भविष्य में शामिल हो सकते हैं। जिसके संबंध में निरंतर चर्चा का दौर जारी है।

हर साल डेढ़ हजार बच्चे ट्रेंड होते हैं

मनीषा यादव, काऊंसलर, सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर, छिंदवाड़ा

छिंदवाड़ा में सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर 2008 में स्थापित हुआ है। इस सेंटर से प्रत्येक साल लगभग 1500 बच्चे ट्रेंड होकर पूरे विश्व में जॉब करने जाते हैं। कमलनाथ जी के प्रयासों से ही यह सेंटर

स्थापित हुआ है और उनके ही प्रयासों से यह जमीन लीज पर ली गई है। भारत में यह एक मात्र सेंटर है। हर एक ट्रेंड में 15 से 25 बच्चों का दाखिला होता हैं। सीएसआर फंड द्वारा इस सेंटर का पूरा खर्चा उठाया है। इस सेंटर का 100 प्रतिशत प्लेसमेंट है और जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं वह भी इसमें दाखिला लेते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेंटर का प्रचार-प्रसार करते हैं। यहां पर ट्रेनिंग पूरी तरह से नि-शुल्क होती है। इस सेंटर में ट्रेनिंग देने वाले सभी लोग बड़ी-बड़ी कंपनियों के लोग होते हैं। यह लोग बच्चों को ट्रेंड करते है

पहुंचे वे सभी छिंदवाड़ा के विकास की गाथा को अपने अनुभवों के साथ नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। 1980 से पूर्व जिस छिंदवाड़ा जिले में पथरीली जमीन के कारण कृषि कार्य पर निर्भर वर्ग को दो वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए ही हर दम

और बताते हैं कि क्या काम करना है। क्या सिखाना है।

दोस्तों से सेंटर के बारे में पता चला

जिया उमर खान, सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर

इस सेंटर के बारे में मुझे दोस्तों के माध्यम से पता चला। मैंने आईटी का डिप्लोमा कम्पलीट कर लिया है। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे रोजगार मिल जायेगा। यहां पर मुझे निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है।

मुझे सोशल मीडिया से सेंटर के बारे में पता चला

मनसू ईवनाती गौंड, सीआईआई स्किल ट्रेनिंग सेंटर

मैं जुन्नारदेव का रहने वाला हूँ। 10वीं पास हूँ। वर्तमान में यहां पर जेसीबी ऑपरेटर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। दोस्तों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस सेंटर के बारे में पता चला।

जूझना पड़ता था, जहां आय के कोई और साधन विद्यमान नहीं थे, और तो और देश के विकसित नगरों एवं महानगरों तक आने-जाने के लिए औसत दर्जे का सड़क मार्ग व रेल मार्ग भी नहीं था, आज वही छिंदवाड़ा जिला विकास के उच्चतम

रिलायंस फाउंडेशन ने बदली किसानों की तकदीर

रिलायंस औद्योगिक समूह द्वारा किसानों, मजदूरों, गरीबों के बीच जाकर सर्वांगीण विकास में भागीदारी निभाने के लिए अक्टूबर 2010 में रिलायंस फाउंडेशन स्थापित किया गया। फाउंडेशन द्वारा कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। फाउंडेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कृषकों के बीच जाकर काम करने के लिए फाउंडेशन की एक टीम देश भर के भिन्न-भिन्न जिलों में गयी। टीम को छिंदवाड़ा जिले के किसानों का कुछ कर दिखाने का जज्बा अतुलनीय लगा। टीम की रिपोर्ट के पश्चात् फाउंडेशन के अधिकारी कमलनाथ से मिले एवं छिंदवाड़ा के विकास पथ पर एक नये आयाम को जोड़ने हेतु रिलायंस फाउंडेशन भी सक्रिय हो गया। फाउंडेशन ने जिले के जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी वहां स्टाप डेम, खेत-तालाब व लिफ्ट एरीगेशन के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई। मोवारि व बिलावल कला गांव में स्थापित लिफ्ट एरिगेशन से लगभग 200 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो गयी है। इसके अलावा 12 स्थानों पर मिट्टी के बांध बनाये गये तथा 08 स्थानों पर सीमेंट-काक्रींट के पक्के स्टाप डेम बनाये गये। स्टाप डेम के कैचमेंट एरिया में सब-सरफेस वाटर के दोहन के लिए 329 कुओं का निर्माण कराया गया। जिसके कारण 725 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों द्वारा डबल फसल ली जाने लगी। तामिया एवं जुन्नारदेव विकासखण्ड में फाउंडेशन द्वारा 12 लाख क्यूबिक मीटर पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए की गयी है तथा 2210 किसानों की कृषि भूमि का समतलीकरण कर उसे उन्नत कृषि योग्य बनाया गया। इसके अलावा कृषकों को बीज उत्पादन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिले के कई कृषक फाउंडेशन के साथ जुड़कर जैविक खाद उत्पादन के माध्यम से अच्छी आय अर्जित करने लगे हैं। फाउंडेशन ने 182 वर्मी कम्पोस्ट पिट एवं 300 नाडेप जैविक खाद के निर्माण के लिए

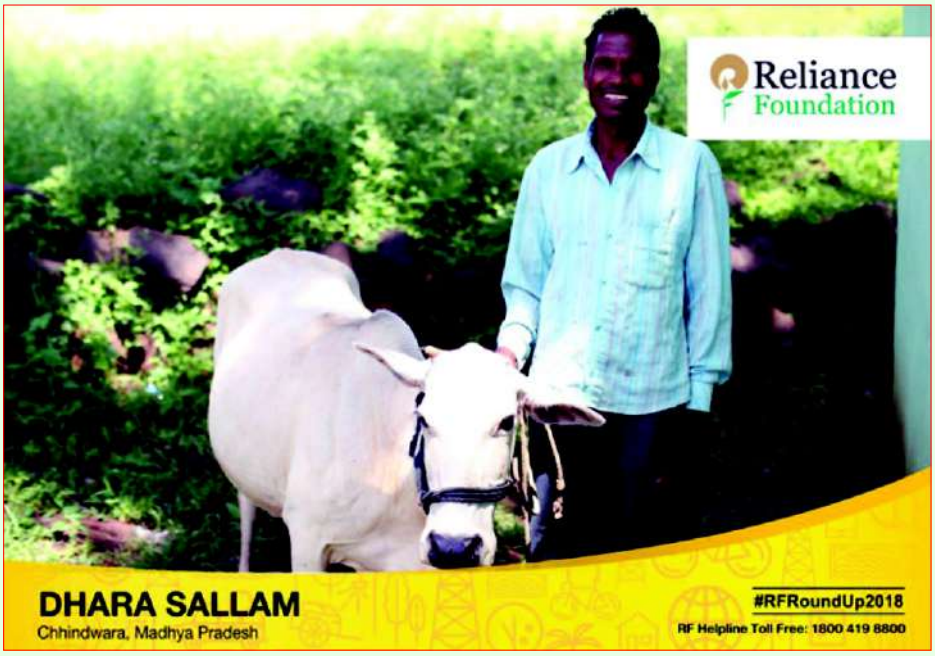

प्रतिमानों के कारण सम्यक विकास के प्रादर्श को केवल मध्यप्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए प्रदर्शित कर रहा है। जो तीव्र विकास दर वाला जिला है, जहां दो सौ से अधिक उद्योग संचालित हैं, जहां प्रदेश के अन्य जिलों में खाली पड़ी जमीन

किसानों को बनाकर दिये हैं। फलों, सब्जियों, एरोमेटिक वनस्पतियों, औषाधीय महत्व की वनस्पतियों की फार्मिंग हेतु फाउंडेशन ने 900 स्थानों पर पोषण वाटिकाएं स्थापित की हैं। दोनों ही विकासखण्डों में सीमांत कृषकों की आय बढ़ाने हेतु कृषकों को भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी पालन का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ सभी प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। रिलायंस फाउंडेशन सरकारी पद्धति से आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने हेतु काम नहीं करता बल्कि छिंदवाड़ा में रिलायंस फाउंडेशन द्वारा कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे कार्यो की इंटीग्रेटेड प्रणाली को देखने व समझने मात्र से अन्य क्षेत्र व अन्य जिलों के किसानों में भी अभूतपूर्व जज्बा पैदा हो जाता है। फाउंडेशन ने दोनों ही विकासखण्डों के 1084 प्रगतिशील किसानों को शेयरधारक बनाकर एक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड स्थापित की है। प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ही 22 गांवों में 22 किसान समितियां बनाई गई हैं। कंपनी स्थानीय कृषकों द्वारा उत्पादित अनाज, फल, सब्जियों, औषधीय महत्व की वनस्पतियों, सुगंधित वनस्पतियों के साथ-साथ खाद, बीज आदि की मार्केटिंग कर रही है। अब तो किसानों की कंपनी का टर्नओवर सालाना दो करोड़ तक पहुंच गया है। अब कंपनी 10 लाख रुपये वार्षिक प्रॉफिट पर चलने लगी है। किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए कमलनाथ की मंशानुरूप रिलायंस फाउंडेशन द्वारा छिंदवाड़ा में किये जा रहे कार्य निःसंदेह सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं।

06 ब्लॉक के 165 गांवों में काम कर रहा है रिलायंस फाउण्डेशन

नीलेश जैन, सदस्य, रिलायंस फाउण्डेशन, छिंदवाड़ा

आजीविकावर्धन कराने, खेती की नई तकनीकों से अवगत कराने, सरकार की एजेंसियों के साथ काम करने, स्किल बढ़ाने के उद्देश्य से रिलायंस फाउण्डेशन छिंदवाड़ा जिले के 06 ब्लॉकों के 165 गांवों में कार्य कर रहा है। यह फाउण्डेशन छिंदवाड़ा में 2010 से काम कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रयासों के कारण ही रिलायंस फाउण्डेशन जिले के इतने गांवों में काम कर रहा है। यह कृषि के अलावा अन्य सोर्सेस पर काम करता है ताकि लोगों को कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों से आमदनी हो। कृषि विज्ञान केन्द्र और हार्टीकल्चर विभाग के साथ मिलकर रिलायंस फाउण्डेशन कृषि में लगने वाले उन्नत बीजों के बारे में जानकारी देता है। इससे किसानों की ग्रोथ बढ़ रही है। फाउण्डेशन की ओर से 10 गांवों के लिए एक वर्कर रहता है। जिसका कार्य लोगों के साथ बैठक करना, ट्रेनिंग देना आदि कार्य होता है। 165 गांवों के अलावा भी और गांवों को जोड़ना है। धीरे-धीरे यह संख्या बढ़ रही है। प्रदेश में छिंदवाड़ा के अलावा, मण्डला, पन्ना, सिवनी, बड़वानी में भी रिलांयस फाउण्डेशन ऐसे ही कार्य कर रहा है। इस फाउण्डेशन का प्रमुख कार्य सेवा करना है। किसानों को समृद्ध करना है।

पर उद्योग स्थापित करने उद्योगपति नहीं आ रहे हैं वहीं छिंदवाड़ा जिले में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योगपति लालायित हैं। जिसका मुख्य कारण जिलावासियों का विकास के प्रति बना सकारात्मक दृष्टिकोण ही है।

आई.एल. एण्ड एफ.एस. : एक ऐसा मंच जहां हुनरवान हो रहे युवा

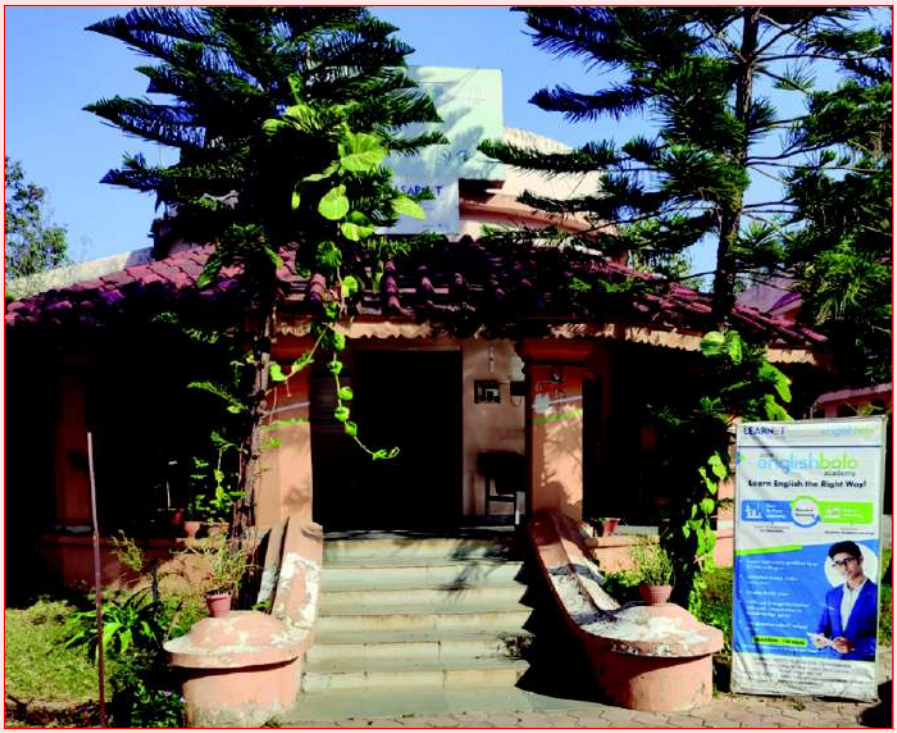

02 नवम्बर 2011 से छिंदवाड़ा में आईएल एंड एफएस द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित किया जा रहा है। जिसमें 30 दिन से लेकर 75 दिन तक के ट्रेनिंग संचालित है। जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फिटर, फूड एंड बेवरेजेस, डोमेस्टिक बीपीओ, सीएमसी आपरेटर, बेकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में मेसन, बार बेन्डिंग आदि के कोर्सेस संचालित हैं। इसके अलावा विकलांग बच्चों के लिए 06 माह के ट्रेनिंग कोर्स तथा आईटीसी होटल्स के साथ मिलकर बेसिक किचन फाउंडेशन स्किल का 06 माह का कोर्स शुरु किया गया है। आईएल एंड एफएस स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर छिंदवाड़ा के सेंटर हेड का कहना है कि छिंदवाड़ा जैसे स्थान में जाकर रोजगारमूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कमलनाथ के कारण ही हुई है। अलग-अलग कोर्सेस के लिए अलग-अलग योग्यता भी निर्धारित है। डिप्लोमा व डिग्रीधारी युवाओं को जॉब नेचर के अनुरुप पूर्णतः प्रायोगिक व कार्य क्षेत्र में जाकर स्वतंत्र रुप से कार्य करने योग्य प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त सेन्टर से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से 84 प्रतिशत को विभिन्न कंपनियों में डायरेक्ट प्लेसमेंट प्राप्त हो जाता है। यही नहीं ट्रेनर्स को भी खुद का कारोबार स्थापित करने में भी अपेक्षित कामयाबी हासिल हो जाती है।

एक ऐसा जिला जो विकास में अव्वल है

यदि हम 2015-16 में छिंदवाड़ा जिले की विशेषताओं को पिछड़े या विकासशील क्षेत्र, कस्बे या जिले के लिए एक आदर्श के रुप में प्रस्तुत करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा जिला दिखाई देता है जहां बिजली के वितरण की समुचित

अंबुजा कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान अमरवाड़ाः जहां हो रहा है शत्-प्रतिशत प्लेसमेंट

अंबुजा सीमेन्ट फाउंडेशन संस्थान द्वारा संचालित 08 कोर्सेस में इच्छानुसार प्रवेश देकर ट्रेनिंग प्रदान कर क्षेत्र विशेष की प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान द्वारा पसारा (प्राइवेट सिक्युरिटी एजेंसी फार रेगुलेटरी एक्ट) के तहत मध्यप्रदेश पुलिस हेड क्वाटर की ओर से सिक्युरिटी गार्ड एवं सुपरवाइजर की ट्रेनिंग प्रदान करने हेतु लायसेंस प्राप्त कर सिक्युरिटी गार्ड एवं सिक्युरिटी सुपरवाइजर की 02 माह की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इस ट्रेनिंग में सिक्युरिटी नार्म्स, हायर सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, फस्ट-एड, सेल्फ डिफेंस (कराटे) आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खास बात यह है कि इस संस्थान से ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट देश की नामी सिक्युरिटी कंपनियों में मिल रहा है। संस्थान में बिजली से चलने वाली जोकी सिलाई मशीन से सुइंग आपरेटर की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इसके साथ- साथ ट्रेनर को डिजिटल मशीन की ट्रेनिंग भी अन्य स्थानों में ले जाकर प्रदान की जा रही है। शर्ट, ब्लाउस, व सूट की सिलाई का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां से ट्रेनिंग प्राप्त ट्रेनर्स को शाही एक्सपोर्ट छिंदवाड़ा व बैंगलोर, ओरिएंट क्राफ्ट दिल्ली जैसे गारमेंट कंपनियों में प्लेसमेंट प्रदान किया जा रहा है। उक्त संस्थान द्वारा दो माह की राज मिस्त्री की ट्रेनिंग भी प्रदान की जा रही है। जिसमें बेसिक मिस्त्री का वर्क, टायलेट मेकिंग के प्रशिक्षण के अलावा कुछ अच्छे प्रशिक्षणार्थियों को नागपुर में अंबुजा सीमेन्ट लिमिटेड द्वारा संचालित एडवांस ट्रेनिंग सेन्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके अलावा 03 से 06 माह की ट्रेनिंग बेसिक हाउस वायरिंग एंड मोटर रिवाइंडिंग तथा फ्रिज, वाशिंग मशीन, फैन, कूलर आदि की वाईडिंग की ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के तहत प्रदान की जा रही है। इस क्षेत्र की कई कंपनियों द्वारा यहां से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्लेसमेंट प्रदान किया जा रहा है। उक्त संस्थान द्वारा 12वीं पास युवाओं को इंग्लिश, कम्प्यूटर एवं साफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण काल सेन्टर मैनेजमेंट के दो माह के कोर्स के तहत प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार संस्थान में 03 माह का व्यूटीशियन कोर्स, 03 माह का कम्प्यूटर टेली कोर्स व तीन माह का कम्प्यूटर हार्डवकिंग व नेटवर्किंग कोर्स भी संचालित है। खास बात यह है कि कमलनाथ ने जिले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के लिए कार्पोरेट सेक्टर में कौशल प्राप्त कर भविष्य संवारने के सुनहरे अवसर प्रदान कर दिये हैं।

व्यवस्था है। जिले के शत-प्रतिशत मध्यम श्रेणी की आबादी वाले गावों में सार्वजनिक नल जल योजनाएं संचालित हैं यानि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगरीय से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक उपलब्ध है। एक ऐसा जिला जहां नगरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक में और तो और सतही क्षेत्र से तीन हजार फीट नीचे पातालनुमा क्षेत्र में स्थापित बसाहटों तक आने-जाने

अशोक लीलैण्ड इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्चः प्रशिक्षण से लेकर प्लेसमेंट तक

देश की सुप्रसिद्ध व्हीकल कंपनी अशोक लीलैण्ड द्वारा भारी वाहनों को चलाने के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी को दूर करने एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध कराने हेतु कमलनाथ के कहने पर लिंगा (छिन्दवाड़ा) नामक स्थान में उच्चतम स्तर के ड्राइविंग स्कूल की स्थापना की गई है। संस्थान में लाइट मोटर ड्राइविंग एवं हैवी मोटर ड्राइविंग का 30-30 दिन का प्रशिक्षण कोर्स संचालित है। दोनों ही कोर्स फुल टाइमर है। प्रशिक्षणार्थियों को 06 से 07 घंटे तक प्रतिदिन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस सेंटर में बस व ट्रक के अलावा ट्रेलर, टिप्पर आदि को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। पृथक से उदय केबिन वाले लम्बे ट्रेलर को चलाने का प्रशिक्षण विशेष तौर पर दिया जाता है। बड़े ट्रेलर के अनुभवी व प्रशिक्षित ड्राइवर को 25 से 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक का वेतन मिलता है। सेन्टर हेड के अनुसार उनके सेन्टर में भारी वाहनों के ड्राइवरों हेतु पूर्व से ही मांग पत्र कई ऑटो मोबाइल कंपनियों द्वारा भेजा जा चुका है। परीक्षा पास करने पर ही प्रशिक्षणार्थियों को सर्टिफिकेट व प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

यह है अशोक लीलेण्ड का ड्राईवर इंस्टीट्यूट, जो छिंदवाड़ा में स्थित है। सीएसआर फंडिंग से यह इंस्टीट्यूट संचालित है। हाई-वे मंत्रालय, कलेक्टर और अशोक लीलेण्ड के एक अधिकारी, तीनों की एक समिति हैं। इस इंस्टीट्यूट लगभग 100 लोगों का एक बैच होता है। एक महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें बड़े-बड़े वाहन चलाने का लायसेंस प्रदान किया जाता है। ड्राईविंग लायसेंस यही से दिया जाता है। मध्यप्रदेश में भारी वाहनों को चलाने का एक मात्र यही इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना 2012 में हुई थी। इसे स्थापित करने में कमलनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी।

के लिए पक्का सड़क नेटवर्क उपलब्ध होने के साथ-साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व पश्चिम के महानगरों को जोड़ने वाले नेशनल हाइवे को जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्गो का सुव्यवस्थित नेटवर्क भी उपलब्ध है। जहां से प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी इंदौर व देश की राजधानी दिल्ली तक आने-जाने के लिए रेलवे की सुविधा

एफ.डी.डी.आई.: नामी कंपनियों में हो रहा प्लेसमेंट

भारत सरकार के सुप्रसिद्ध तकनीकी शिक्षा संस्थान फुट वियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की देश भर में कुल 08 ब्रांचेस हैं। तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ ही इस संस्थान को उच्च कोटि का स्किल डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट भी माना जाता है क्योंकि उक्त संस्थान में क्षेत्र-विशेष के नामी कंपनियों में उत्कृष्ट स्तर की सेवा देने लायक स्किल्स तैयार किये जाते हैं। 2010 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को यह सौगात उपलब्ध कराई। निश्चित रूप से इस संस्थान के माध्यम से छिंदवाड़ा का नाम रोशन हो रहा है। फुट वियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में इस संस्थान के पास आउट टेक्नोट्स की मांग सर्वाधिक है। छिंदवाड़ा स्थित संस्थान में अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम संचालित है। फुट वियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट तथा रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेन्टाइजिंग में यू.जी. व पी.जी. पाठ्यक्रम संचालित है। दोनों ही पाठ्यक्रमों यू.जी. में 60-60 सीट तथा पी.जी. में 30-30 सीट उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि एफ.डी.डी.आई. पूर्व में केवल डिप्लोमा कोर्सेस ही संचालित करता था। 12वीं के बाद दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले छात्र दोनों ही पाठ्यक्रमों में से किसी में भी डिप्लोमा कोर्स में भाग ले सकते थे। इसी प्रकार दोनों ही पाठ्यक्रमों में ग्रेजुएशन के बाद पी.जी. डिप्लोमा कोर्स संचालित था। बाद में इग्नू के साथ एम.ओ.यू. करके एफ.डी.डी.आई. ने दोनों ही पाठ्यक्रमों में यू.जी. व पी.जी. डिग्री कोर्स शुरू कर दिया है। लेकिन खास बात यह है कि इग्नू द्वारा दी गई डिग्री से कहीं अधिक महत्व एफडीडीआई के डिप्लोमा का होता है। जिसके कारण दोनों ही डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को क्रमशः यू.जी. व पी.जी. डिग्री के साथ यू.जी. व पी.जी. डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है। छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में 22 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित एफ.डी.डी.आई. के संस्थान में फुट वियर्स इंडस्ट्री की आधुनिकतम मशीनों में काम करने का अवसर यहां अध्ययनरत छात्रों को प्राप्त होता है। जिसके कारण उनके समक्ष डिग्री व डिप्लोमा की प्राप्ति के पश्चात प्लेसमेंट को लेकर किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं होती।

उपलब्ध है। यदि कोई उद्योगपति या वीआईपी छिंदवाड़ा आना चाहे तो उसके विमान को उतारने के लिए एयर स्ट्रीप की सुविधा भी उपलब्ध है। यानि परिवहन व आवागमन की दृष्टि से उत्तम स्थिति उपलब्ध है। जहां मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा व विदर्भ के नागपुर जिले की जीवनरेखा के रुप में मान्य पेंच नदी पर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक भूमि की सिंचाई के

एफडीडीआई का अवलोकन करती जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक, कार्यकारी संपादक समता पाठक और जिला स्किल डेवलपमेंट कोआर्डीनेटर आतिश ठाकरे

लिए बांध का निर्माण किया जा रहा है। जहां अन्य नदियों कन्हान, कुल बेहरा आदि पर सिंचाई के लिए पर्याप्त बांध बने हैं। हजारों ट्यूबवेल स्थापित कर ग्राऊंड वाटर का अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है अर्थात् सिंचाई की सुविधा की दृष्टि से भी संतोषजनक स्थिति उपलब्ध है। एक ऐसा जिला जहां किसान पूरी तरह आधुनिक कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। हाईब्रिड किस्म के बीजों से उत्पादन रिकार्ड उपलब्धियों के साथ हो रहा है। गन्ना व गेहूं के उत्पादन में भी अग्रणी स्थिति बन गई है। सोयाबीन, अरहर व अन्य उत्पादनों में भी बहुत बढ़िया स्थिति

कृषि, उद्यानिकी और सब्जी उत्पादन में अव्वल छिन्दवाड़ा

बड़े-बड़े उद्योगों से मिल रहे रोजगार

है। उद्यानिकी के क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थिति है। यहां नागपुरी संतरे का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। कपास उत्पादन में भी रिकार्ड उपलब्धि हासिल कर ली है। एक एकड़ का भूमिधारी किसान वर्ष भर में दो से तीन लाख रुपये की आय सब्जियों के उत्पादन से प्राप्त कर रहा है। जहां पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, टमाटर सहित कई प्रकार की सब्जियों का रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। सब्जियों के उत्पादन के लिए किसानों ने अत्यंत आधुनिक कृषि उपकरणों एवं टेक्नोलॉजी को अपनाया है। हिन्दुस्तान यूनीलीवर, रेमण्ड व ब्रिटानिया जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स के

अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर: कमलनाथ के प्रयासों से खुला संस्थान

छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेन्टर संचालित है। जिसकी स्थापना कमलनाथ के प्रयास से सन् 2008 में की गई। यह संस्थान भी देश का उत्कृष्ट दर्जे का स्किल डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट माना जाता है। जिसका संचालन कपड़ा मंत्रालय के प्रोजेक्ट के तहत अपेरल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल द्वारा किया जा रहा है। यहां अपेरल डिजाइनिंग से संबंधित आधुनिकतम मशीने एवं उत्कृष्ट स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध है। इस संस्थान में तीन माह से लेकर दो साल तक के सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स एवं तीन साल के पाठ्यक्रम से युक्त डिग्री कोर्स संचालित है। यहां तीन माह या सौ घंटे के 10 कोर्स संचालित हैं। जिसमें सुइंग मशीन आपरेटर, मशीन टेक्नीशियन जैसे कोर्स शामिल हैं। चार माह के गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को जॉब अपार्चुनिटी

प्रोडक्शन सेंटर तथा 200 से अधिक उद्योग स्थापित व संचालित हैं। जहां फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। जहां सभी प्रकार के फलों से पाउडर बनाये जा रहे हैं। अदरक, प्याज, लहसुन व हल्दी के भी पाउडर से तैयार हो रहे है। जहां टमाटर, मक्के व वनोपज के रुप में प्राप्त चिरोंजी की औद्योगिक स्तर पर फुड प्रोसेसिंग कर विदेशों में सप्लाई की जा

की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार एक वर्षीय कोर्स प्रोडक्शन सुपरविजन एंड क्वालिटी कंट्रोल तथा अपेरल पैटर्न मेकिंग (बेसिक) के 06 माह के कोर्स को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संस्थान द्वारा एक वर्ष व दो वर्ष के 15 डिप्लोमा कोर्स संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें अपेरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, अपेरल फैशन डिजाइनिंग, पैटर्न मेकिंग विथ कैड (साफ्टवेयर) शामिल है। खास बात यह है कि इस संस्थान के प्रत्येक कोर्स से पास आउट छात्रों को शत-प्रतिशत प्लेसमेंट देश के नामी टेक्सटाइल एवं गारमेंट इंडस्ट्री में प्राप्त हो रहा है। छिंदवाड़ा स्थित अपेरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेन्टर द्वारा छिंदवाड़ा जिले के हरई, न्यूटन, पाण्डुर्णा एवं अमरवाड़ा में संचालित ट्रेनिंग कैम्प में तीन-तीन माह के कोर्स संचालित हैं।

सात हजार युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ा- सतीश पटेल, सेंटर हेड एटीडीसी, छिंदवाड़ा

2007 में कमलनाथ जी के प्रयासों से छिंदवाड़ा में एटीडीसी सेंटर स्थापित हुआ है। अब तक सेंटर से 11 हजार से अधिक युवक युवतियों को ट्रेंड किया जा चुका है। 7000 को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार से जोड़ा जा चुका है। यह पूर्णतः फैशन और गारमेंट्स का ट्रेनिंग सेंटर है। इसके शुभारंभ में तत्कालीन कपड़ा मंत्री दयानिधि मारन आए थे और उन्होंने ने ही इसका शुभारंभ किया। वर्तमान में यहां पर लगभग 125 युवक युवतियां ट्रेनिंग ले रही है। यह सब यहां पर निःशुल्क होता है। रहने खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। सेंटर में अधिकतर आदिवासी बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। बड़े उत्साह के साथ बच्चे आते हैं। आज यह बच्चे यह हुनर न सीखते तो अन्य जगहों पर

रही है। जहां फूड पार्क है, स्पाइस पार्क है, संतरे व अन्य फलों को दो माह तक सुरक्षित रखने, सार्टिंग व पैकिंग करने की सुरक्षित व्यवस्था उपलब्ध है। सात केन्द्रीय विद्यालय के अलावा मॉडल विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों के अलावा हर गांव व कस्बे तक शिक्षा

जाकर मेहनत-मजदूरी करते। बच्चों की भी सोच बदली है। वह आत्म-निर्भर होना चाहते हैं। कमलनाथ जी का भी यही प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे सेंटर से लाभांवित हो।

हर तीन महीने में एटीडीसी में प्लेसमेंट होता है- भूमिका बेलबंशी

हमारे सेंटर में हर तीन माह में प्लेसमेंट होता है। देशकी बड़ी-बड़ी कंपनिया प्लेसमेंट के लिए आती है। यहां पर फ्री में ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है। 06 माह तक कोर्स होता है। एटीडीसी स्पांसर मिलना पक्का है। यह सब कमलनाथ जी के प्रयासों से हो रहा है। दूर-दूर से बच्चें दाखिला लेते हैं। यहां ट्रेनर स्थानीय है। मेरे पापा खुद एक डिजाईनर है।

यहां आकर बहुत कुछ सीखने को मिला- अस्मिता सोनेकर

इस सेंटर में आकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे गांव में एक महिला का स्व-सहायता समूह है वहां से मुझे पता चला कि फैशन डिजाईनर का एक कोर्स फ्री में कराया जाता है। मैं इसमें दाखिला लेकर आत्म-निर्भर बनना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ।

सीखने के साथ जॉब भी मिलती है- सरस्वती उईके

मैं सोंसर की रहने वाली हूँ। महिला स्व-सहायता समूह से मुझे इस सेंटर के बारे में पता चला। मेरी बुआ की लड़की यहां से ट्रेनिंग लेकर बेंगलुरु में जॉब कर रही है। मेरा यहां लास्ट मंथ है। मैं भी जॉब करने बाहर जाऊंगी।

की उत्तम व्यवस्था, ट्रेडिशनल कोर्सेस के जिले भर में 15 शासकीय कॉलेज तथा 28 निजी कॉलेज, 02 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 01 इंजीनियरिंग कॉलेज, 06 शासकीय आई.टी.आई. व 26 निजी आई.टी.आई. संचालित हैं तथा मेडिकल कॉलेज स्थापित होने जा रहा है। छिन्दवाड़ा देश में सर्वश्रेष्ठ स्किल डेवलपमेंट हब के रूप में स्थापित हो चुका

एजिस कॉल सेन्टरः 1200 लोगों का काल सेंटर छिन्दवाड़ा में

एस्सार ग्रुप के चेयरमैन अंशुमान रुईया जब कमलनाथ से मिले तो कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने लायक उपक्रम शुरु करने की बात उनके समक्ष रख दी। जब श्री रुईया ने बताया कि उनके समूह द्वारा संचालित एजिस काल सेन्टर यदि छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया तो एक हजार से भी अधिक शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। छिंदवाड़ा के औद्योगिक क्षेत्र इमलीखेड़ा में 2012 में एस्सार ग्रुप के चेयरमैन अंशुमान रुईया की उपस्थिति में कमलनाथ ने एजिस सेंटर का उद्घाटन किया। वर्तमान में उक्त सेंटर में 1200 एसोसिएट्स कार्यरत हैं। 1200 एसोसिएट के अलावा अप्रत्यक्ष रुप में कम से कम 500 लोगों को भी एजिस काल सेन्टर के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो रहा है। निःसंदेह छिंदवाड़ा वासियों के लिए यह गर्व की बात है कि देश भर में आधार कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन या नये आधार कार्ड बनवाने का काम केवल दो ही संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। जिसमें छिंदवाड़ा स्थित एजिस काल सेंटर एवं हैदराबाद स्थित करवी काल सेंटर ही शामिल है। सबसे अधिक काम की जिम्मेदारी एजिस काल सेंटर को ही सौंपी गई है।

स्टारटेक का सेंटर 2012 में छिंदवाड़ा में खुला है। इसमें एयरटेल का कस्टमर केयर सेंटर चल रहा है। पूरे भारत में एयरटेल का हिन्दी भाषी कस्टमर केयर सेंटर है। जिसमें लगभग 1200 लड़किया काम करती है। जिसमें ज्यादातर जरुरतमंद लड़कियों को काम दिया जाता है। यह सेंटर कमलनाथ जी के कारण आया है। इसमें काम करने वाली लड़कियां आसपास के गांवों की होती है। जो काम करने के लिए यहां आती है।

है जहां फुट वेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट, एपेरल टेक्सटाइल डिजाइन सेंटर के अलावा सी.आई.आई. अंबुजा सीमेन्ट, अशोक लीलैण्ड, एन.आई.आई.टी. जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों के स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित व संचालित है। जिसके कारण युवा शिक्षित बेरोजगारों को जॉब नेचर के अनुरुप ट्रेनिंग प्राप्त कर राष्ट्रीय व बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट प्राप्त

टाटा कॉल सेन्टर अम्बाड़ाः सेवाएं दे रहे स्थानीय नागरिक

परासिया के निकट ग्राम अम्बाड़ा में टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा कॉल सेन्टर स्थापित किया गया है। उक्त कॉल सेन्टर को 500 सीटर बनाने की योजना है। जनवरी 2013 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन सायरस मिस्त्री ने कमलनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के जरुरतमंद एवं शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर मिस्त्री ने उन्हें आश्वस्त किया वे छिंदवाड़ा जिले में टाटा बिजनेस सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड की ओर से संचालित कॉल सेन्टर की स्थापना करेंगे। वर्तमान में काल सेंटर में आधार कार्ड से संबंधित शिकायतों के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त कॉल सेंटर के उद्घाटन समारोह में टाटा ग्रुप के चेयरमैन साइरस मिस्त्री भी शामिल हुए थे।

टेक्सटाइल पार्कः किसानों को मिल रहा लाभ

केन्द्र में कपड़ा मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई। हालांकि इससे पूर्व ही उनके प्रयास से रेमण्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध कम्पनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर बोरगांव में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन रेमण्ड का रॉ मटेरियल बाहर से आता है। जबकि छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना व सौंसर क्षेत्र में वर्षो से कपास की खेती हो रही है। इसलिए कमलनाथ की इच्छा थी कि कॉटन बेस्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिले में स्थापित की जाए। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में एडवाइजरी कमेटी के तत्कालीन चेयरमैन प्रेम मलिक से कमलनाथ ने इस विषय में चर्चा की तो मलिक ने कमलनाथ की भावनाओं को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े बड़े उद्योगपतियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने टेक्सटाइल किंग के नाम से प्रसिद्ध मुकुन्द चौधरी से इस विषय में चर्चा की। उसके पश्चात् श्री चौधरी व श्री मलिक कमलनाथ से मिले एवं उन्होंने टेक्सटाइल पार्क की अवधारणा को मूर्तरुप प्रदान करने के लिए अपनी योजना से अवगत कराया। टेक्सटाइल क्षेत्र के नामी उद्योगपतियों प्रेम मलिक, मुकुंद चौधरी, कपिल चौधरी, संतोष शिधाये, अमित हरिलाल रुपरेलिया, संजीव धवन, निकुंज कुमार श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद, नवेदुल इस्लाम खान व गौरव गुप्ता ने मिलकर सीएलसी टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई।

करने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

प्रायमरी स्कूल के मामले में छिंदवाड़ा जिले में आदर्श स्थिति

जनवरी 1980 में सांसद निर्वाचित होने के बाद फरवरी 1980 में सम्पूर्ण संसदीय क्षेत्र के दौर के दौरान कमलनाथ ने बिजली, पेयजल, सड़क, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ अत्यंत विषम

पातालकोट: पाताल तक पहुंची पक्की सड़क

पातालकोट छिन्दवाड़ा का प्रमुख क्षेत्र है। पातालकोट को जानने, समझने की उत्सुकता हर एक भारतीय नागरिक की होती है। जैसे कि इसके नाम से ही समझा जा सकता है कि यह जगह काफी नीचे है और इसमें निवास करने वाले लोग देश-दुनिया से कटे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पूरी हो गई है।

केवल छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सघन वनाचंल से घिरा हुआ है सतपुड़ा पर्वत पर स्थित तामिया विकासखण्ड के सतपुड़ा पर्वतमाला की घाटियों से घिरे लगभग तीन हजार फीट गहराई में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित पातालकोट क्षेत्र में दो से तीन किलोमीटर के अंतराल के बीच भारिया व गौंड जनजाति के रहवासियों के 12 गांव स्थित हैं। ऊपर से देखने पर उस ऊंची पहाड़ी से नीचे, आबादी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां लोग कैसे रहते होंगे, उन्हें उनकी जरुरत की चीजें कैसे मिलती होगी। क्या पहनते होंगे। क्या खाते होंगे। बाहर आते-जाते कैसे होंगे, जैसे सवाल आंखों के सामने खड़े हो जाते है।

स्थिति शिक्षा के साधनों में भी महसूस करी। उन्होंने देखा कि छोटे-छोटे बच्चे हाथ में थैले के समान बैग लेकर 05 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। स्कूलों की स्थिति के बारे में जब उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि 4-5 गांव के बीच में एक प्रायमरी स्कूल है। इन स्थितियों में 6-7 साल की उम्र के बच्चे किस तरह पढ़ने जाते होंगे। आज की परिस्थितियों में

पातालकोट के निवासियों से चर्चा करती हुई संपादक विजया पाठक

इन सब सवालों के जवाब लगभग 30 साल पहले अत्यंत कठिनाई से मिल पाते थे। अब सवाल के आगे समस्या नहीं दिखती बल्कि समाधान प्रस्तुत हो जाता है। यह क्षेत्र अत्यंत गुणकारी वनौषधियों के कारण समृद्ध है। गुजरात के तो एक कारोबारी ने यहां उपलब्ध वनौषधियों के लिए अपने कर्मचारी तक नियुक्त कर रखे हैं। घाटी के ऊपर चढ़ने पर पहला गांव कठौतिया मिलता है। वहीं के निवासी मेहताब शाह ने बताया कि पूर्व में पातालकोट के आदिवासी लगभग तीन से चार किलोमीटर का सफर खड़ी पहाड़ी को चढ़ कर पूरा करते थे। उन्होंने अपने हिसाब से पगडंडिया बना रखी थी। पेड़ों की जड़े, कुछ नीचे तक झुके हुए पेड़ों के तने एवं महुआ व अन्य वनस्पतियों के बेले के सहारे वे घाटी को चढ़कर ऊपर तक आ पाते थे। ऊपर आने पर कठौतिया से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर उन्हें छिन्दी नामक कस्बाई बाजार मिलता था। खासकर वे साप्ताहिक बाजार के दिन ही आते थे। घाटी के नीचे तक स्कूल तो था नहीं। जिसके कारण पढ़े-लिखे होने का सवाल ही नहीं उठता था। इलाज तो वे जड़ी-बूटियों से ही करते थे। अब भी वे बीमार होने पर अधिक

अत्यंत सोचनीय विषय हो सकता है। मिडिल स्कूल तो सम्पूर्ण विकासखण्ड में 04 या 05 ही हुआ करते थे। 10 से 15 किलोमीटर दूरी तक के छात्र मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। हाईस्कूल तो सम्पूर्ण विकासखण्ड में एक या दो ही हुआ करते थे। कमलनाथ ने सार्वजनिक शिक्षा की इस दुरावस्था को अत्यंत कष्टकारी मानते हुए यह संकल्प लिया कि प्रत्येक गांव व प्रत्येक

विश्वास जड़ी-बुटियों पर ही करते हैं। महिलाएं ऊपरी वस्त्र नहीं पहनती थी। पुरुष व महिलाएं दोनों ही लंगोट लगाते थे। कुछ पुराने लोग तो पेड़ों के पत्तों व छाल का उपयोग तन ढकने के लिए करते थे। महुआ के पत्ते, महुआ के बेले की रस्सी तथा छिन्द के पत्तों से बनाई कई चटाईयां आदिवासी छिन्दी के बाजार में बेचने लाते थे। लकड़ी व कुछ वनौपजों को वे बाजार में बेचते थे तथा उससे मिट्टी का तेल, कुछ कपड़े और नमक खरीदते थे। तीज- त्यौहार के अवसर पर महिलाएं मोटे-मोटे आभूषण पहनती थी। उन आभूषणों के व्यापारी भी छिन्दी के बाजार में आते थे। 1980 तक संभवतः कोई भी विधायक स्तर का नेता पाताल कोट नहीं गया था। वास्तव में

वर्तमान में पातालकोट में क्षेत्र के आखरी गांव कारेगांव तक पक्की सड़क बन चुकी है। बिजली पहुंच चुकी है। जिसके कारण अब यहां पर पर्यटक काफी संख्या में पहुंचने लगे हैं। जिससे स्थानीय लोगों को लाभ मिल रहा है। आदिवासियों की वन औषधी बिकने लगी हैं।

बसाहट में प्रायमरी स्कूल, पैदल चलकर जाने लायक की दूरी पर मिडिल स्कूल एवं अधिकतम 05 किलोमीटर की दूरी पर हायर सेकेण्डरी स्कूल जब तक नहीं होगा तब तक शत-प्रतिशत शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करना संभव ही नहीं है, वे उस लक्ष्य को हासिल करने हेतु अधिक से अधिक स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे। 1980 से 85 के बीच हर माह में 08-10

पातालकोट के विभिन्न क्षेत्रों में शासकीय भवनों (स्कूल, पंचायत भवन, आँगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केन्द्र आदि) का निर्माण हो रहा है। धीरे-धीरे क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। लोगों को भी शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

आदिम संस्कृति व आदिम जीवनशैली के दर्शन अगर कहीं हो सकते थे तो वह क्षेत्र पातालकोट ही था। आदिम संस्कृति एवं रहन-सहन, तीज-त्यौहार, प्राकृतिक आबोहवा की दृष्टि से यह क्षेत्र अब भी इको टूरिम के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। 2012 की जनगणना के अनुसार 75 प्रतिशत गौंड व 25 प्रतिशत भारिया जनजातीय आबादी वाले पतालकोट क्षेत्र में कुल जनसंख्या 2013 है। यहां चिमटीपुर, गुजा डोंगरी, सहरा पंचगोल, हर्रा कछार, सुखानीमनी झरम पालानी, घाटलिंगा, गुडीचाटरी, कारयाम, रातेड,

नये स्कूल खोले जाने की जानकारी उनके कार्यालय में आ जाती थी। एकाएक म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश आ जाता था। जबकि उससे पहले स्कूल खोलना साधारण बात नहीं थी। प्रति एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल, तीन किलोमीटर के दायरे में मिडिल स्कूल एवं आठ किलोमीटर के दायरे में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने का प्रावधान तो

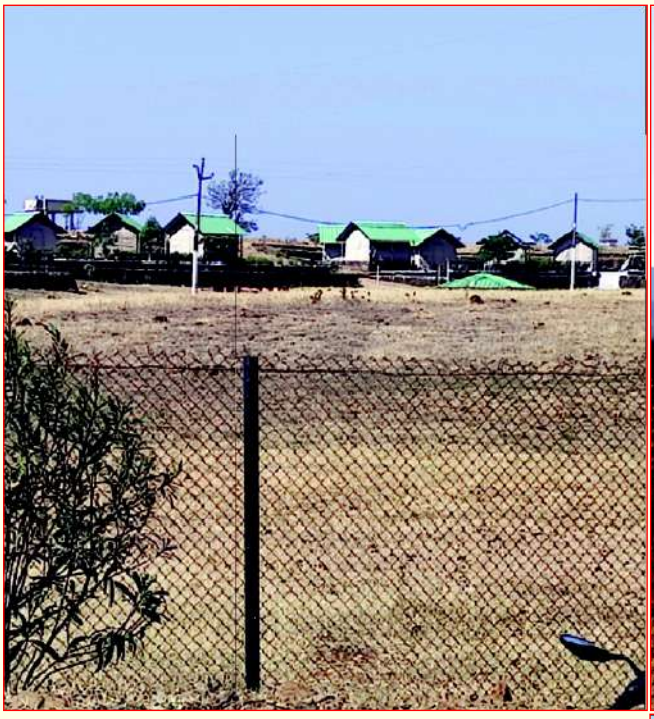

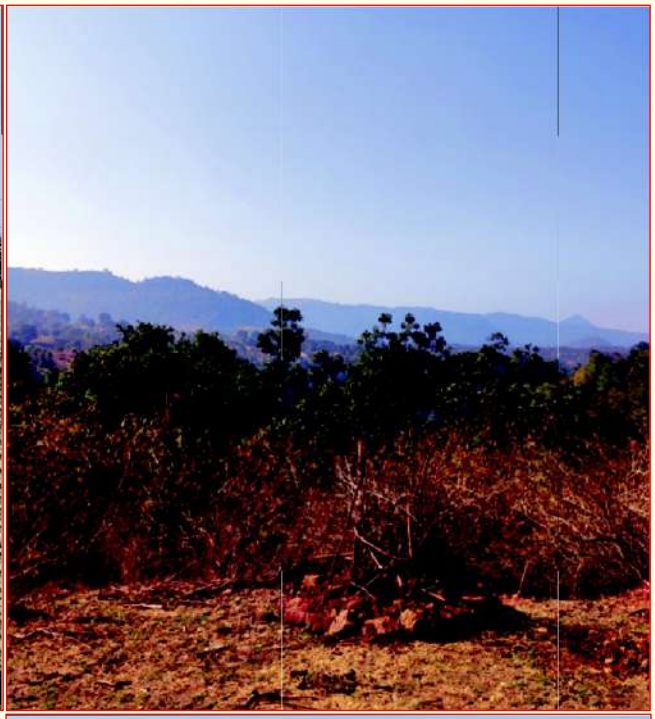

ये है पातालकोट के ऊपर नव निर्मित यूरेका एडवेंचर कैम्प। जहां से पातालकोट का दिखने वाला विहंगम दृश्य मनमोहक है। कैम्प बनने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिला है।

जलदुब्बा, जड़ मांदल व खमाटपुर आदि गांव दो से तीन किलोमीटर के अंतराल में स्थित है। इनमें से 12 गांव में ही आबादी है। शेष गांव वीरान हैं। 1981 में कमलनाथ पहली बार पातालकोट आए तथा उन्होंने वहां के आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे ऊपर तक अर्थात छिन्दी गांव तक सड़क बनवायेंगे। स्कूल खोलने एवं स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया। 1980 के दशक में ही कमलनाथ ने पातालकोट के गांवों तक बिजली पहुंचाने हेतु बजट की व्यवस्था एवं निर्माण की स्वीकृति दिला दी। होशंगाबाद, पिपरिया, तामिया (विकासखंड मुख्यालय) वाले राजमार्ग से 24 किलोमीटर की

काफी समय बाद केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरुप किये गये। लेकिन उससे काफी पहले ही अत्यंत पिछड़े छिंदवाड़ा जिले में गांव-गांव में स्कूल खोलने का सिलसिला शुरु हो गया था। जहां भी जाते थे वहां स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरु हो जाती थी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के रिकार्ड के अनुसार कुल 3044 बसाहटें हैं। आज की स्थिति में कुल 2685

पातालकोट के सभी क्षेत्रों में बिजली की समुचित व्यवस्था हो गई है। जगह-जगह ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई गई है।

दूरी पर स्थित कस्बाई बाजार के रूप में ख्याति प्राप्त छिन्दी नामक गांव तथा छिन्दी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोंगरा नामक गांव व वहां से 14 किलोमीटर लम्बा पहाड़ी को काटते हुए रास्ता बनाकर चिमटीपुर-कारेगाम व रातेड़ तक पक्की डामरीकृत सड़क का निर्माण कराया गया है। कमलनाथ अब पातालकोट के हर गांव तक पक्की सड़क बनाकर उसे इस सड़क से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। पातालकोट के ही जलदुब्बा व घाटलिंगा नामक गांव में पक्की सड़क बनाई जा चुकी है। अब तो पर्यटक पातालकोट आकर पैदल चलने वाले रास्ते का भी आनंद लेते हैं। पैदल चलने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता मेन रोड पर स्थित विजयदाना के पास से तीन किलोमीटर नीचे की ओर उतरकर ग्राम रातेड़ से होकर जाता है। इस रास्ते में एक किलोमीटर तक तो पक्की सड़क है। लेकिन उसके बाद दो किलोमीटर के रास्ते में कुछ कच्ची तो कुछ पक्की सीढ़िया हैं। इस प्रकार पैदल रास्ते में दूसरा रास्ता ग्राम छिन्दी से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम कठौतिया व वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित फारेस्ट रेस्ट हाउस से होकर जाता है। फारेस्ट रेस्ट हाउस तक पक्की सड़क है। उसके बाद दो किलोमीटर घाटी से नीचे की ओर पैदल चलकर पातालकोट के चिमटीपुरा गांव तक पहुंचा जा सकता है।

बसाहटों में प्राईमरी स्कूल संचालित हैं। प्राईमरी स्कूल के मामले में छिंदवाड़ा जिले में आदर्श स्थिति बन चुकी है। जिले में कुल 1041 मिडिल स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। वर्तमान में जिले में कुल 329 हाई व हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं। जिले में 04 केन्द्रीय विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं तथा जुन्नारदेव, सौंसर व पाण्डुर्णा में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो

पातालकोट को विश्व में पहचान दिलाई कमलनाथ जी ने- नवीन मरकाम, (जिला पंचायत सदस्य छिंदवाड़ा)

नवीन मरकाम से विजया पाठक की बातचीत

आज पातालकोट में जो विकास हुआ है और विश्व में जो पातालकोट जाना जाता है उसमें इस क्षेत्र के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समय पातालकोट अत्यंत पिछड़ा और मुख्यधारा से कोसो दूर था। इस क्षेत्र के हजारों आदिवासी भाईबहिन मुख्यधारा से कटे हुए थे। यहां पर न बिजली थी, न सड़क थी, न शासन की योजनाएं थी लेकिन कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया और बिजली पानी सड़क जैसी सुविधाएं लोगों को मिलने लगी हैं। पातालकोट नाम रेलगाड़ी का संचालन करवाया है। यहां के लोगों के लिए मुख्य सड़क का निर्माण कराया जा रहा है जो पातालकोट के अंतिम छोर तक के गांव को जोड़ती है। इसके अलावा कई शासकीय भवनों का निर्माण कराया है, जिससे जहां के निवासियों को लाभ मिल रहा है।

गौरतलब है कि पातालकोट में तीन पंचायतों से कुल 12 गांव आते हैं। पूरा क्षेत्र पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों से प्राप्त जड़ी-बूटियों के अलावा वनोपज आंवला, हर्रा, महुआ, चिरौंजी, गौंद, बर्रा, भेड़ा, गुठली आदि ही इन लोगों की आजीविका का साधन हैं। यहां के निवासी इन जंगलों से जड़ी-बुटियां लाते हैं और सड़क किनारे बैठकर इन को बेचते है। अब इन्हें बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ताकि इन वनोषधियों को बेचने के लिए एक नियत स्थान मिल सके। इन जड़ी-बूटियां बहुत ही कारगर हैं। जो बड़ी-बड़ी बीमारियों में लाभदायक हैं। हमारा प्रयास है कि इन बूटियों के लिए एक बाजार का निर्माण करना है। यदि इन लोगों को बाजार उपलब्ध हो जाए तो निश्चित ही इन लोगों की आय अधिक होने लगेगी। वर्तमान में पातालकोट में सड़क बन जाने से अब अन्य पर्यटक पातालकोट के अंतिम छोर तक पहुंचने लगे हैं।

चुकी है। इस प्रकार जिले में कुल सात केन्द्रीय विद्यालय स्थापित हो जायेंगे जो कि प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक हैं। जिले में एक नवोदय विद्यालय एवं दो एकलव्य विद्यालय भी सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम में संचालित है। जिले में प्रत्येक ब्लाक में एक-एक मॉडल स्कूल एवं एक-एक एक्सीलेंस स्कूल भी संचालित हैं।

उच्च व तकनीकी शिक्षा में

वनोपज बेचकर जीवन यापन करते हैं- बिसनलाल भारती (भारिया समुदाय), ग्राम रातेड़, पातालकोट

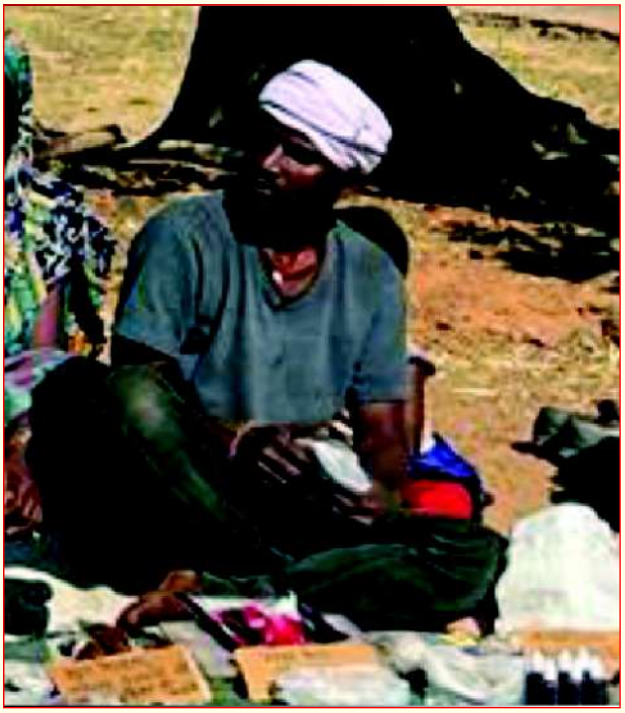

दादा परदादा के जमाने से हम यहीं पर रह रहे है। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने हमारे क्षेत्र में काफी काम कराया है। जड़ी-बूटियां बेचकर जीवन यापन करते हैं। हमारे यहां पानी की बड़ी समस्या है। खासकर गर्मियों में परेशानी होती है। सड़क, बिजली आ गई हैं अब पानी की समस्या भी हमारे नेता खत्म कर देंगे।

हम पातालकोट को छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे- राजकुमार खमरिया, ग्राम रातेड़, (पातालकोट)

यहां के जंगल ही हमारी आय के साधन हैं। इन जंगलों से प्राप्त जड़ी-बूटियां बेचना हमारा पेशा है। इसके अलावा थोड़ी-बहुत खेती भी करते हैं। हमारे नेता कमलनाथ जी ने हमारे क्षेत्र में काम किया है। सड़क का निर्माण हो रहा है, जिससे आवागमन सुगम हुआ है। पानी

की समस्या है। इस पर भी काम होना चाहिए।

सड़क बनने से काफी लोग पाताल कोट आने लगे हैं। गुड्डी (भारिया), ग्राम रातेड़, (पातालकोट)

हमारे यहां की सड़क बनने से यहां तक कई लोग घूमने आने लगे हैं। हमारी जड़ी-बूटियां भी बिकने लगी हैं। हम लोग खेती-बाड़ी का काम भी करते हैं। जंगलों से महुआ, गुठली बीनते हैं और बेचते हैं।

कमलनाथ जी ने लाईट लगवाई हैं- बालचन्द्र भारती, (भारिया), ग्राम कारेगांव, (पातालकोट)

कमलनाथ जी ने हमारे गांव में लाईटें लगवाई हैं। अब सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क बनने से इस क्षेत्र में काफी फर्क पड़ा है। क्षेत्र के आखरी गांव को सड़क से जोड़ा जा रहा है। आने-जाने में सहूलियत हुई है।

अग्रणी- जिले में उच्च शिक्षा के लिए भी प्रयास किये गये। छिंदवाड़ा जिले में 1980 तक केवल छिंदवाड़ा व परासिया में ही महाविद्यालय संचालित थे। 11 विकासखंड मुख्यालयों के अलावा उमरानाला, चांद एवं लोधीखेड़ा नामक स्थानों में भी शासकीय महाविद्यालय स्थापित किये गये। अब छिंदवाड़ा जिले में 15 शासकीय महाविद्यालय एवं 28 निजी महाविद्यालय

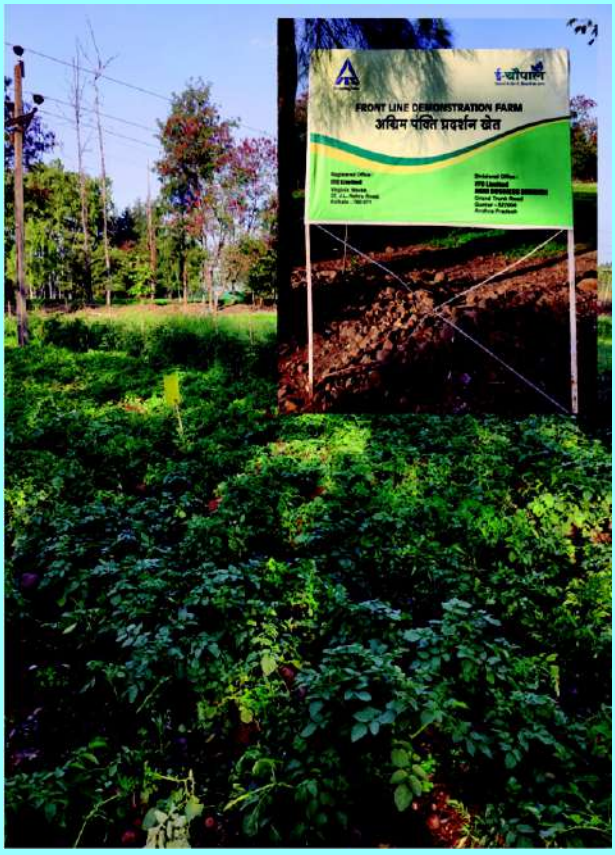

यह सागर चौपाल का क्षेत्र है। जहां पर 23 एकड़ खेत में उन्नत तकनीकी से विभिन्न फसलों को उगाया जाता है। साथ ही क्षेत्र के किसानों को इन उन्नत तकनीकों के बारे में बताया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी।

संचालित हैं। जिले में छिंदवाड़ा व सियालडोह में पॉलिटेक्निक कॉलेज संचालित है। इसके अलावा 01 गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज छिंदवाड़ा में भी संचालित हैं। जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा में एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज भी संचालित है। मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का विधिवत शिलान्यास कर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया। छिंदवाड़ा जिले में 06 शासकीय आईटीआई है। जिसमें 01 महिला आईटीआई और 01 ट्राइबल आईटीआई भी शामिल है। इसके अलावा 26 प्राइवेट आईटीआई भी जिले में संचालित हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में तो छिंदवाड़ा देश का अग्रणी जिला है। जिले में

प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में भी छिन्दवाड़ा अव्वल है। छिन्दवाड़ा जिले में उच्च शिक्षा के कई शैक्षणिक संस्थान स्थापित है, जहां से युवा शिक्षा प्राप्त कर देश भर में जॉब प्राप्त कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से संबंधित इंजीनियरिंग कॉलेज एवं इसी क्षेत्र में डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान स्थापित करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक जिला बना छिंदवाड़ा

सन 1980 से पूर्व जहां छिंदवाड़ा जिले को आसपास के जिलों से कटा हुआ, विकास की मुख्यधारा से हटा हुआ, सघन वनांचल से युक्त, कम उपजाऊ, पथरीली जमीन वाला, उद्योगविहीन, अत्यंत पिछड़ा

जिला माना जाता था। वहीं अब यह जिला म.प्र. का सबसे अग्रणी औद्योगिक जिले की श्रेणी में स्थान बना चुका है। जिले के सौंसर विकासखण्ड में महाकौशल का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर व बोरगांव फूड पार्क स्थापित है। पांडुर्ना विकासखण्ड में फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन आयल इंडस्ट्री. मोहखेड़ विकासखण्ड में फुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जिला मुख्यालय छिंदवाड़ा विकासखण्ड में कई लार्ज स्केल, मीडियम स्केल व स्माल स्केल उद्योग, चौरई विकासखण्ड में अदानी समूह द्वारा स्थापित किया जा रहा निर्माणाधीन पावर प्लांट, जुन्नारदेव व परासिया विकासखण्ड में डब्ल्यूसीएल की कोयला खदानें एवं कोल वाशरी तथा तामिया, अमरवाड़ा व हर्रई विकासखंड में केन्द्रीय पादप बोर्ड द्वारा संचालित वनौषधियों के उत्पादन, चिरौंजी जैसे ड्राय फ्रूट के प्रोसेसिंग से संबंधित उद्योग संचालित है। यह जिला कृषि उत्पादन में तो अग्रणी स्थान प्राप्त कर ही चुका है। अब औद्योगिक दृष्टि से भी सबसे विकसित जिला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1980 से पूर्व छिंदवाड़ा जिले में जुन्नारदेव व परासिया क्षेत्र में कोयला खदान मंडल संचालित थे लेकिन कोल इंडिया की कंपनी डब्ल्यूसीएल द्वारा पूर्व से संचालित कोयला खदानों में कोल डिपोजिट्स की कमी को देखते हुए लगातार कोयला खदानों को बंद किया जा रहा था। जिसके कारण कोल इंडस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के सामने पलायन की स्थिति निर्मित हो गई थी। जिले में कृषि उत्पादन तो अत्यंत कम ही था। मूंगफली, जगनी व अलसी के उत्पादन के कारण छिंदवाड़ा एवं पाण्डुर्णा में कुछ आइल मिलों का संचालन स्थानीय उद्यमियों द्वारा किया जा रहा था। जिले में उद्योगों के नाम पर शून्यवत स्थिति थी। प्रति व्यक्ति आय अत्यंत अल्प थी। उद्योगों की स्थापना के लिए ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर था और ना परिवहन के साधन उपलब्ध थे। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरुप सुविधाएं प्रदान कर जिले में अनुकूल वातावरण बनाने का सफल प्रयास किया। जिसके कारण आज छिंदवाड़ा को देश-विदेश में अभूतपूर्व प्राप्त हो चुकी है।

वर्तमान समय में छिन्दवाड़ा प्रदेश के अन्य शहरों से कम नहीं हैं। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार, पानी, उद्योग जैसे बुनियादी सुविधायें अपेक्षाकृत हैं। निश्चित रूप से छिन्दवाड़ा जिले को जो पहचान मिली है उसमें इस क्षेत्र के नेता कमलनाथ का महत्वपूर्ण योगदान है। 1980 से लेकर आज तक वह अजेय हैं तो इसका प्रमुख कारण उनका इस क्षेत्र के प्रति लगाव और मेहनत हैं। यही कारण है कि आज छिन्दवाड़ा को कमलनाथ का छिन्दवाड़ा कहा जाता है। सही मायने में यदि ऐसी सोच और लक्ष्य देश के अन्दर अन्य नेता भी रखे तो राजनीति के मायने ही अलग हो जाते हैं।

क्या चुनाव जीतने और दमन-अत्याचार के लिए भूपेश बघेल का अस्त्र है रासुका?

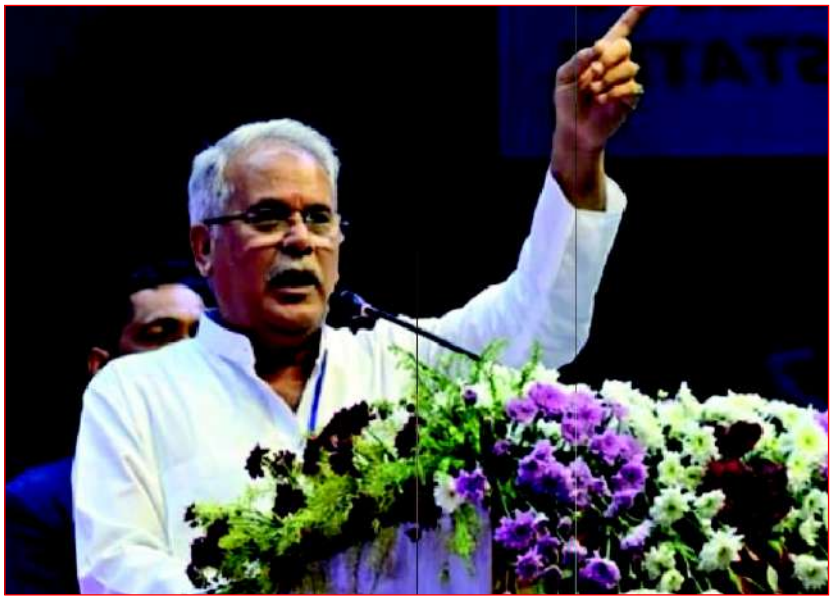

भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों ने पिछले चार साल सिर्फ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और लूटपाट मचाई। अब प्रदेश में जनता की सुरक्षा का हवाला देते हुए और खुद को जनता का हितैषी बताने के लिए भूपेश बघेल ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है।

विजया पाठक

दिनांक 03 जनवरी को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के इतिहास में एक काला अध्याय स्थापित कर दिया है। इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक तरीके का घोषित आपातकाल मतलब

छत्तीसगढ़ में एक तरीके का घोषित आपातकाल, जो भी खिलाफ लिखेगा-बोलेगा, वह जेल जाएगा

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली सरकार के पसीने अभी से ही छूटने लगे हैं। भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों ने पिछले चार साल सिर्फ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और लूटपाट मचाई। अब प्रदेश में जनता की सुरक्षा का हवाला देते हुए और खुद को जनता का हितैषी बताने के लिए भूपेश बघेल ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। जबकि राज्य के भीतर वर्तमान समय में इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी। राज्य में रासुका का लगना साफ तौर पर भूपेश बघेल की तानाशाही की ओर इशारा करता है। जाहिर है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में रासुका के जरिए एक बार फिर से आपातकाल लगाने की साजिश रची है। अब इस कानून को लागू करने का असली मकसद क्या है इस पर गौर करना जरूरी है।

पिछले कुछ दिनों से भूपेश बघेल और उनकी चांडाल चौकड़ी पर केंद्रीय एजेंसियां ने नकेल कस रखी है। साथ-साथ मुझ जैसे कुछ एक पत्रकार, समाजसेवी इनकी काली करतूतें लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को जाहिर कर रहे थे। इनकी चांडाल चौकड़ी के प्रमुख सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी अभी जेल में हैं, स्वयं भूपेश बघेल और विनोद वर्मा अभी जमानत पर हैं जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और

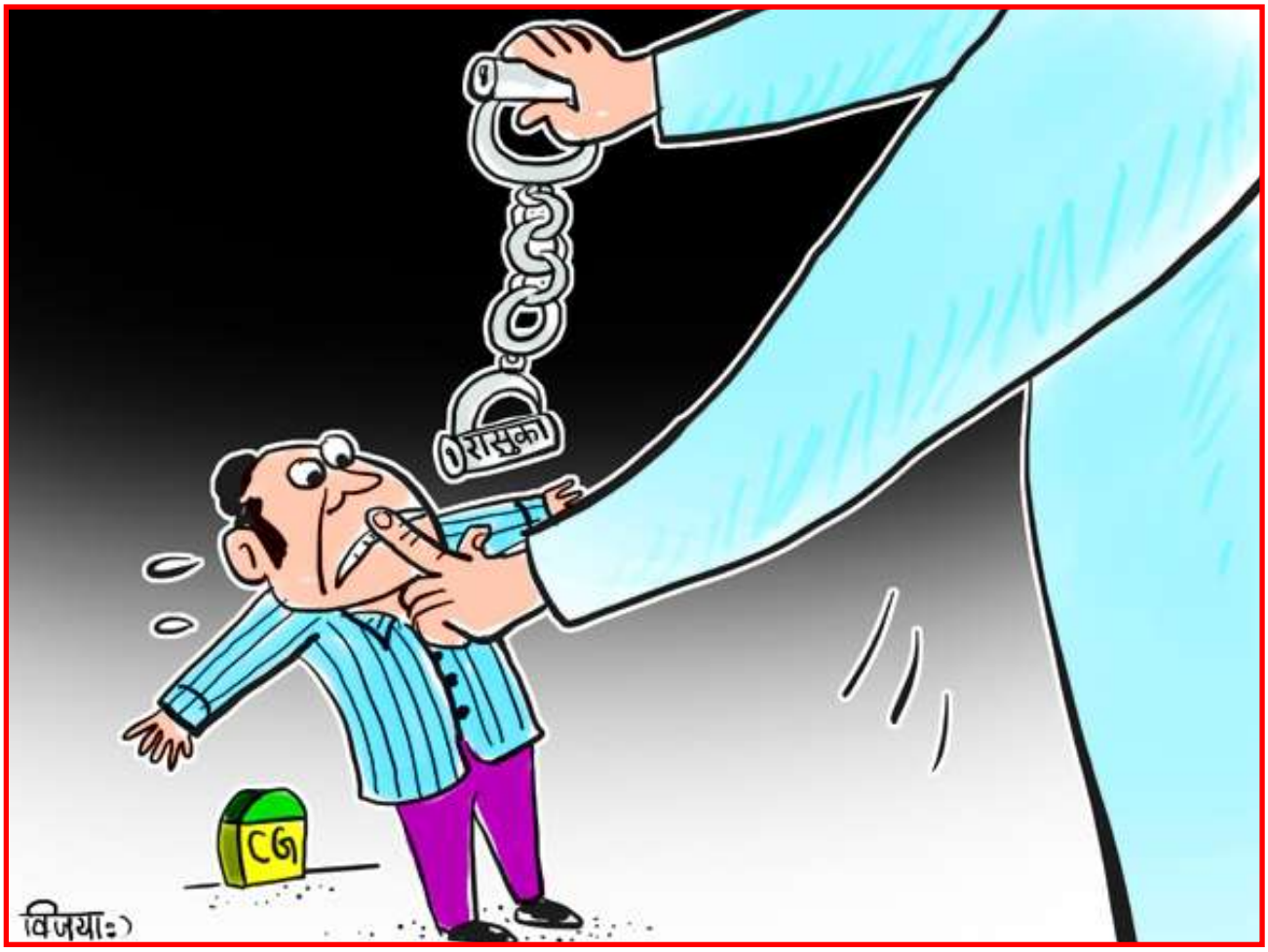

इनकी जमानत कभी भी खारिज हो सकती है। अनिल टुटेजा पर भी कयास लग रहे हैं कि यह भी ईडी की जद में आने वाले हैं। नान घोटाले में भी इनकी जमानत खारिज हो सकती है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के पुत्र चेतन बघेल भी ईडी की जांच में शामिल हैं और इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में अपने विरोधी और मुझ जैसे पत्रकारों की आवाज चुनाव तक दबाने का अस्त्र ही है छत्तीसगढ़ का नया घोषित आपातकाल। वैसे मेरे घर विनोद वर्मा के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस को मेरे खिलाफ अवैधानिक तरीके से डिटेंशन की कोशिश 25 दिसंबर को की जा चुकी है।

आज छत्तीसगढ़ के हालत सूडान से भी

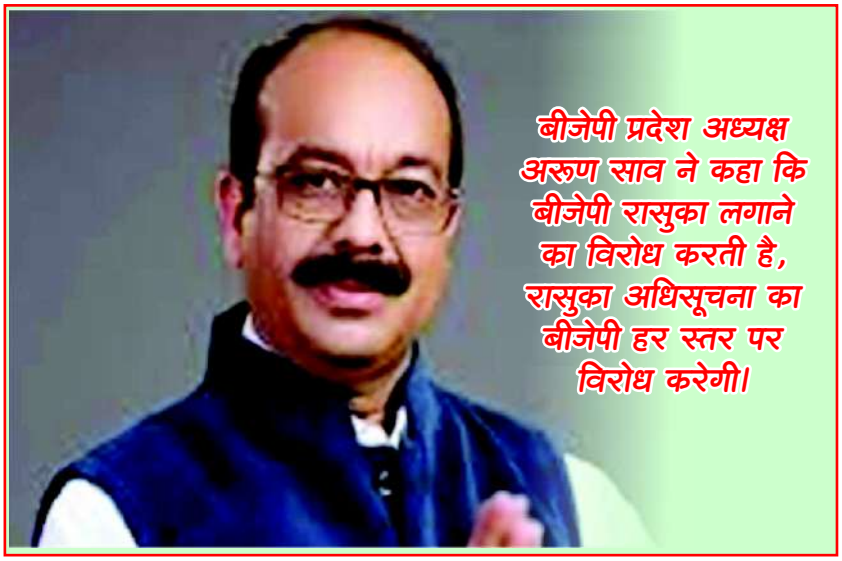

ज्यादा खराब हो गए हैं। यह भूपेश और इनकी चांडाल चौकड़ी ने भय-अत्याचार-दमन-भ्रष्टाचार की सरकार पिछले चार वर्ष से चला रखी है। आदिवासी, सतनामी सभी पिछड़े समाजों का जमकर शोषण हुआ। अब जब चुनाव पास आ गए हैं तो भूपेश अपने खिलाफ उठती हर आवाज दबाना चाहते हैं।

अपनी कुर्सी बचाने के लिए कितना और गिरेंगे बघेल

सरकार आदिवासियों को दबाने में लगी है, ताकि चुनाव में यह समाज डर के कारण इनके खिलाफ ना जाए। मुख्यमंत्री ने अघोषित आपातकाल लागू करने की शुरुआत लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए कानून बनाकर काफी पहले कर दी थी लेकिन इससे जनता के सभी वर्गो का आक्रोश दोगुना हो गया। इससे घबराकर उन्होंने रासुका के बहाने आपातकाल जैसी अलोकतांत्रिक स्थिति का निर्माण कर दिया है। रासुका लगाने का सीधा आशय भूपेश सरकार की नाकामयाबी और विफलता से है।

भुगतना पड़ सकता है इसका खामियाजा

सूत्रों की मानें तो भूपेश बघेल के कैबिनेट मंत्री खुद ही मुख्यमंत्री के इस निर्णय से सकते में हैं। उनका कहना है कि वर्तमान समय में राज्य के अंदर ऐसी कोई सुरक्षा से जुड़ी समस्या नहीं है जिससे कि राज्य के अंदर रासुका लगाने जैसी कोई नौबत आये। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह निर्णय लिया है तो निश्चित ही इसका नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को होगा। कई मंत्रियों ने यह भी कहा है कि अभी भी समय है अगर भूपेश बघेल आगे भी अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं उन्हें रासुका को तत्काल प्रभाव से राज्य से हटा देना चाहिए।

रासुका का निर्णय नहीं रहा पक्ष में

पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भूपेश सरकार राज्य में अघोषित आपातकाल लागू कर लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। रासुका के बहाने आपातकाल जैसी अलोकतांत्रिक काम करने में लगे हुए हैं। सीएम भूपेश से कुर्सी नहीं संभल रही है तो, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को अधिसूचित करना चाहिए। वह प्रदेश में एक धर्म विशेष को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं

पूर्व देश में आपातकाल की बात हो या फिर रासुका की। यह इतिहास रहा है कि जिस भी नेता ने देश में या राज्य में रासुका या आपातकाल लगाया है वो दोबारा सत्ता में नहीं लौटा। ऐसा ही कुछ आगाम विधानसभा चुनाव में बघेल के साथ होने का अंदेशा पार्टी नेताओं ने अभी से ही लगाना शुरू कर दिया है।

क्या भयावह वातावरण के सहारे जीत पाएगी भूपेश बघेल?

कांग्रेस यह डींगें हांकती है कि प्रदेश में सब कुछ समान्य है, फिर रासुका क्यों लगाया है। अपने मूल दायित्व को निभाने में सरकार विफल हुई है। कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति की पोल खुल गई है। यह लोकतंत्र विरोधी कानून है। भाजपा इसे लेकर एक रैली करने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह के साथ साथ राजेश मूणत ने कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो रासुका खत्म करेंगे और मतांतरण रोकने के लिए कानून लाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री बघेल कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सवाल प्रदेश की गंभीर स्थिति निर्मित करने का काम भूपेश बघेल और इनकी चौकड़ी ने किया है। आज मेरे जैसे पत्रकार जो इनके काले कारनामे उजागर करते है उनके साथ प्रदेश में कुछ भी ही सकता है। इनकी स्थिति यह है की सरकार के खिलाफ बोलने पर बस्तर की आंदोलनकारी सोनी सोढ़ी की घर की बिजली काट दी गई और जब यह बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पत्रकार वार्ता में उठा उसके एक घंटे में बिजली लाइन जोड़ दी गई। इसके बाद राहुल गांधी ने इस यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ में आकर उनके कुशासन देखने की बात की। शायद घोषित आपातकाल का एक कारण यह भी हो।

अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तल्खी से बीजेपी को फायदा

समता पाठक

राजस्थान में अभी भी गहलोत सरकार में सब कुछ ठीकठाक नही चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वॉर समय रहते सामने आ ही जाता है। जबकि राज्य में अब विधानसभा को लेकर एक साल से भी कम समय बचा है। ऐसे में राज्य के दोनों प्रमुख नेताओं के बीच मनमुटाव से चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं सरकार में सचिन पायलट की लगातार अनदेखी की जा रही है। राजस्थान में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे कांग्रेस के दो दिग्गजों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खुल कर एक-दूसरे के सामने आ गए हैं। कोई किसी को कोरोना कह रहा है तो कोई सीधे अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहा है। ऐसे में लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस के सामने एक बार फिर साल 2020 जैसा संकट खड़ा हो सकता है। जब सचिन पायलट खुलकर गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए थे। और ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में गहलोत सरकार गिर जाएगी। लेकिन गहलोत और आलाकमान की वजह से दोनों के बीच मामला संभल गया था। लेकिन पिछले महीनों से जिस तरह दोनों नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे लगता है कि मामला आने वाले दिनों में तल्खी बढ़ेगी।

कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बार-बार आश्वासन दे रहा है कि उन्हें उचित मान सम्मान मिलेगा। प्रदेश की राजनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मगर कांग्रेस आलाकमान द्वारा

विधायकों के इस्तीफे से सकते में थी सरकार

राजस्थान की राजनीति में इस समय 91 विधायकों का इस्तीफा देना विवाद का विषय बन गया है। कहने को ये इस्तीफे पिछले साल 25 सितंबर को दिए गए थे, लेकिन उसके बाद से स्थिति काफी बदल चुकी है। ये सभी विधायक अपने इस्तीफे वापस ले चुके हैं।

क्या है ये पूरा मामला? - जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में इससे पहले भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तब कोर्ट ने अपनी तरफ से विधानसभा सचिव और अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था। तब तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी तक राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में अब 30 जनवरी को होने वाली सुनवाई को निर्णायक माना जा रहा है। वैसे यहां ये समझना जरूरी है कि पिछले साल एक साथ 91 कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से इस्तीफा दे दिया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चुनाव चल रहे थे, सीएम अशोक गहलोत रेस में सबसे आगे थे। लेकिन उनके उस प्रमोशन से राजस्थान में कांग्रेस विधायकों को डर था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में तब 91 विधायकों ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जब वो विवाद थम चुका है, गहलोत भी शांत पड़ गए हैं तो सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे को वापस लेने का मन बनाया। लेकिन उस फैसले पर अभी तक विधानसभा स्पीकर की तरफ कुछ नहीं कहा गया है। अब कोर्ट में इसमें क्या रुख दिखाता है, इसका इंतजार करना होगा।

पायलट को ताकतवर बनाने की दिशा में अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पाई है। इससे सचिन पायलट का भी धीरज जवाब देने लगा है। इसीलिए वह एक बार फिर मुखर होकर बयान देने लगे हैं। कुछ दिनों पूर्व सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब में राहुल गांधी से मिलकर राजनीतिक चर्चा की थी। उसके बाद लौटकर उन्होंने राजस्थान में जाट बहुल नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली व जयपुर में बड़ी-बड़ी जनसभाएं कर अप्रत्यक्ष रूप से गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पायलट की मीटिंगों में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहें हैं। हर जगह पायलट ने बेरोजगारों, युवाओं, किसानों, दलितों व पीड़ितों के पक्ष में बातें रखकर गहलोत सरकार को घेरने का काम किया है। सचिन पायलट की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को देखकर गहलोत के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को तुरंत प्रदेश के दौरे पर रवाना कर जन समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। पायलट को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि गहलोत के सामने कांग्रेस आलाकमान बेबस हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चाहे पायलट के धैर्य की कितनी भी तारीफ करें। गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत पायलट को बार-बार कांग्रेस से बगावत करने वाले नेता के तौर पर कठघरे में खड़ा करते रहते हैं। मगर गहलोत द्वारा स्वयं ही पार्टी आलाकमान के निर्देशों को नहीं मानकर खुलेआम बगावत करने की घटना को गहलोत मात्र एक छोटी सी भूल बताकर उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सचिन पायलट को गहलोत अभी तक भी गुनाहगार मानते आ रहे हैं। सचिन पायलट ने जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यशैली के खिलाफ बगावत की थी तब उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री के पद से तथा उनके समर्थक तीन मंत्रियों महाराजा विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा को तत्काल पद से बर्खास्त कर दिया गया था। पायलट की नजरों में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पायलट समर्थक सैनिक कल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का कहना है कि 2013 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते उनके नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। जिसमें कांग्रेस 200 में से

सचिन पायलट की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़ को देखकर गहलोत के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने अपने मंत्रियों को तुरंत प्रदेश के दौरे पर रवाना कर जन समस्याओं को सुलझाने के निर्देश दिए हैं। पायलट को यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि गहलोत के सामने कांग्रेस आलाकमान बेबस हो रहा है।

महज 21 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी थी। जबकि 2018 में सचिन पायलट कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तब कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते 100 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। ऐसे में उस वक्त 200 में से 21 सीट जीतने वाले को तो मुख्यमंत्री बना दिया गया था। जबकि 200 में से 100 सीट जीतने वाले को उप मुख्यमंत्री ही बनाया गया था। पायलट के साथ उस समय किया गया भेदभाव अभी तक जारी है।

नकल करवाने वाले गिरोह के सरगनाओं को नहीं पकड़ा जा रहा है। राजस्थान में पिछले 4 साल में 14 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों के साथ बड़ा धोखा हो रहा है। पायलट का मानना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि पेपर तिजोरी में बंद रहते हैं तो फिर बंद तिजोरी से पेपर कौन से जादू के बल पर आउट हो रहे हैं। सचिन पायलट द्वारा यह एक तरह से सीधा मुख्यमंत्री अशोक

कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी। मगर चार साल बीत जाने के बाद भी वसुंधरा राजे के खिलाफ आज तक किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की गई है। वसुंधरा राज के जिन घोटालों पर हमने आरोप लगाए जिनके सबूत हैं। मगर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि केंद्र सरकार गांधी परिवार को बेवजह परेशान कर रही है और राजस्थान में हमारी सरकार बीजेपी राज के घोटालों पर कार्रवाई नहीं करती? यह मिल बांटकर सत्ता सुख भोगने

सचिन पायलट ने अपनी रणनीति बदल ली है। हालांकि सचिन पायलट के पास सत्ता नहीं रहने के कारण विधायकों की संख्या कम है। विधायकों के संख्या बल पर ही मुख्यमंत्री गहलोत आलाकमान से अपनी हर बात मनवा लेते हैं। ऐसे में सचिन पायलट का पूरा फोकस युवा वर्ग पर हो गया है। सचिन पायलट गहलोत शासन में सरकारी परीक्षाओं के लगातार पेपर आउट होने पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। पायलट ने तो यहां तक कह दिया कि पेपर

गहलोत पर निशाना साधा जा रहा है। पायलट के बयानों को युवाओं में भारी समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते पायलट जहां भी जाते हैं बड़ी संख्या में नौजवान उनका समर्थन करने पहुंच रहे हैं। हाल ही में पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। पायलट ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वसुंधरा राज्य के मुख्यमंत्री

की राजनीति का हिस्सा नहीं तो और क्या है? इन परिस्थितियों में कांग्रेस आलाकमान को तेजी से निर्णय लेना होगा। यदि समय रहते पायलट व उनके समर्थकों को राजस्थान की राजनीति में पर्याप्त महत्व नहीं मिलता है तो अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में बने रहने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाएगी। समय रहते कांग्रेस आलाकमान को इस गंभीर विषय पर विचार करना होगा।

आम बजट-2023

गरीब, किसान और ग्राम कल्याण का चुनावी बजट

मुफ्त अनाज योजना होगी चुनावी जीत की मास्टर स्ट्रोक

प्रमोद भार्गव

विशुद्ध रूप से यह चुनावी बजट है। इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसके ठीक 5 माह बाद आम चुनाव है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पूर्ण बजट है। इसलिए यह बजट हर वर्ग के व्यक्ति के लिए रियायती बजट है। आयकर में 7 लाख तक कि छूट देकर नौकरीपेशा बड़ी राहत का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि 5 साल में यह राहत पहली बार मिली है। लेकिन कोरोना के बाद जिस तरह से खानपान जैसी हर वस्तु में कर के प्रावधान किए गए हैं, उससे तय है कि प्रत्यक्ष कर के रूप में दी जाने वाली अप्रत्यक्ष कर के रूप में वापस ले लेगी। इस प्रावधान के चलते बचत के रूप में बैंक और डाकघरों में भी राशि ज्यादा जमा होगी। इसी दौरान घरेलू गैस और रेल सुविधा पर जो सब्सिडी मिलती थी, वे सब सरकार ने लगभग खत्म कर दी हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष लाभ देना चुनावी साल में देना जरूरी था। बावजूद यह बजट गरीब, किसान, मजदूर और ग्राम के लिए कल्याणकारी है। इस बजट में 80 करोड़ 35 लाख लोगों को एक साल के

लिए मुफ्त अनाज देने का दो लाख करोड़ से ज्यादा का बजट प्रावधान कर दिया है। मोटे अनाज, जैविक कृषि से लेकर किसान को डिजिटल प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा व पुस्तकालय के प्रबंध किए हैं। गोया यह बजट अनुशासित होने के साथ राजनीति और अर्थनीति के बीच आश्चर्यजनक संतुलन पैदा करने वाला बजट है। इसमें चतुर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी रेवड़ियां भी बांट दीं और अर्थव्यवस्था को नुकसान भी नहीं होने दिया।

केंद्र सरकार गरीबों को पूरी तरह निशुल्क अनाज देने का प्रबंध करके ऐसा चुनावी दांव चल दिया,जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि एक साल, यानी दिसंबर 2023 तक बढ़ाकर पेट की भूख से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी है। यह योजना दिसंबर 2022 को समाप्त हो रही थी। हालांकि फिलहाल चल रही इस योजना में सस्ती दरों पर अनाज राशन की दुकानों पर उपलब्ध कराया जाता था। इसमें चावल तीन रुपए किलो,गेहूं दो रुपए और मोटा अनाज एक रुपए किलो दिया जा रहा था। यह अनाज पूरी तरह मुफ्त होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभी तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे सामान्य परिवारों को प्रतिव्यक्ति पांच किलो अनाज हर महीने निशुल्क दिया जाता है। जबकि अंत्योदय वर्ग के उपभोक्ताओं को अनाज की यह मात्रा सात किलो प्रति व्यक्ति होती है। मसलन प्रत्येक सामान्य परिवार को 25 किलो और अंत्योदय परिवार को 35 किलो अनाज हर महीने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 81.35 करोड़ लोगों को रियायती दरों पर अनाज दिया जा रहा है। इस सुविधा पर दो लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुफ्त अनाज 2023 में नौ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में लाभदायी है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर के मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं। इसके बाद 2024 मई जून में लोकसभा के चुनाव भी होना है। यानी भाजपा इन राज्यों में विजयश्री हासिल कर लेती है तो इस मुफ्त योजना को 2024 के लिए भी बढ़ाया जाना तय है।

कोरोना महामारी के दौरान जब काम-धंधे पूरी तरह बंद हो गए थे, तब रोज कुआं खोदकर प्यास बुझाने वाले लोगों के लिए भोजन का संकट गहरा गया था। अतएव भारत सरकार ने गरीबों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से पूर्व से मिल रहे सस्ते अनाज के अतिरिक्ति पांच किलो मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था तीन महीने के लिए शुरू की थी। उम्मीद थी कि तीन माह बाद कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका सुरसा-मुख लंबे समय तक खुला रहा। इसलिए इस अवधि को क्रमशः बढ़ाया जाता रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने और अनिश्चित आय वालों के लिए यह अन्न योजना संजीवनी का काम करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू है। गरीबों अथवा भूखों को मिले इस सस्ते अनाज के अधिकार को इस कानून का उज्जवल पक्ष माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में देश के लोग भूखे हैं, तो यह चिंता का विषय है कि आजादी के अमृत महोत्सव में भी यह भूख क्यों बनी हुई है। अतएव सरकार ने मोटा अनाज पैदा करने के लिए जो प्रोत्साहन के प्रावधान किए हैं, उनमें यदि मध्यान्ह भोजन और मुफ्त अनाज योजनाओं के लिए किसान से मोटा अनाज खरीद कर भोजन के प्रबंध कर दिए जाएं तो किसान वास्तव में ज्वार,बाजरा, रागी, मक्का जैसी फसलें पैदा करने लग जाएगा।

यूपी की राजनीति में वर्चस्व खोते जा रहे छोटे दल

मणिशंकर पाण्डे

पिछले कई वर्षो से भारतीय जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और बसपा अपने-अपने स्तर पर ज़ोर-आजमाइश कर प्रदेश में शासन कर रही हैं। वही राज्य के छोटे दल अपने आप को स्थापित करने में नाकाम होते जा रहे हैं। एक समय था कि इन छोटे दलों का वर्चस्व काफी था। लेकिन अब राज्य में इन छोटे दलों का वर्चस्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। यही कारण है कि इन दलों के नेताओं ने राज्य के ताकतवर दलों के साथ गठबंधन की नीति अपना ली है। इन दलों में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक दल, डॉ संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल शामिल हैं। लेकिन पिछले तीन विधानसभा चुनावों के नतीजों पर नज़र डालें तो एक बात के संकेत मिलते हैं कि उत्तरप्रदेश में मतदाता किसी एक पार्टी को बहुमत दे रहे हैं और 403 विधानसभा सीटों वाले इस राजनीतिक रूप से जटिल प्रदेश में पूर्ण बहुमत के लिए 202 सीटें जीतना ज़रूरी है। साल 2007 के चुनाव ने मायावती को 206 सीटों के साथ सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, 2012 के चुनाव ने अखिलेश यादव को 224 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बनाया और 2017 में 312 सीटों के साथ योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- राजभर समुदाय के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने साल 2017 में राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके चार सीटें हासिल की थीं। और इस चुनाव के बाद से अशोक राजभर की महत्वाकाँक्षाएं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को गहराई से समझने वाले मानते हैं कि जब-जब बड़ी पार्टियां छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर चुनाव में जाती हैं तो छोटे दलों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन इन दलों के नेता बड़ी पार्टियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। अगर पिछले चुनाव में राजभर बीजेपी के साथ नहीं लड़ते तो ये चाहे कितना भी दावा करें तो इनकी मौजूदगी राजनीतिक सफलता के लिहाज़ से नहीं दिखती। अब मसला ये है कि वह पिछले चुनाव में इतनी सीटें जीत चुके हैं तो उन्हें राजनीतिक सफलता दिखती है। साल 2002 में स्थापित होने वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश की लगभग दो दर्जन सीट पर माना जाता है। हालांकि, ओम प्रकाश राजभर दावा करते हैं कि उनका समाज प्रदेश की लगभग 100 सीटों पर अपना प्रभाव रखती है।

अपना दल- उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से विशेषतः वाराणसी और इसके आसपास के क्षेत्र में कुर्मी वोटरों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में है। कांशीराम के साथ काम कर चुके डॉ. सोने लाल पटेल ने साल 1995 में

अपना दल की स्थापना की थी। लेकिन इस समय अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल हैं। प्रदेश में चार ऐसे तबके हैं जिनकी मौजूदगी पूरे उत्तर प्रदेश में है। इनमें ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और मुसलमान शामिल हैं। इनके अलावा अन्य जातियों के अलग-अलग इलाके हैं। और इन इलाकों के अपने नेता हैं। जैसे कुर्मी बाराबंकी से लेकर बहराइच तक हैं, बनारस से लेकर सोनभद्र तक हैं, फतेहपुर से लेकर बुंदेलखंड तक हैं। लेकिन यूपी में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो इन तीनों जगहों पर कुर्मियों का नेता रहा हो। बाराबंकी से बहराइच तक बेनी प्रसाद वर्मा थे, बनारस में सोनेलाल पटेल रहे और अब अनुप्रिया पटेल हैं। ऐसे में ये जातियां अपने नेता बदलती रही हैं।

राष्ट्रीय लोकदल- प्रदेश की राजनीति में ये इतिहास रहा है कि जब-जब यूपी में राष्ट्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं तो इसका नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों को उठाना पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर मेरठ, मुजफ़्फ़रनगर और बिजनौर आदि इलाकों में प्रभाव रखने वाला राष्ट्रीय लोकदल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। साल 2014 और 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की धमक का सबसे ण्यादा राजनीतिक नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को ही उठाना पड़ा है। चौधरी अजीत सिंह ने साल 1996 में इस पार्टी का गठन किया था। इसके बाद से धीरे-धीरे पार्टी ने ज़मीन पर अपनी जगह बनाई थी। साल 2002 की बसपा सरकार में आरएलडी को दो कैबिनेट मंत्री पद हासिल हुए थे। इसके बाद साल 2004 के चुनाव में आरएलडी ने तीन लोकसभा सीटें हासिल कीं। इसके 10 साल बाद 2014 में आरएलडी ने यूपीए के झंडे तले चुनाव लड़ा और सारी सीटें गंवा बैठी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने सिर्फ 01 सीट जीती और आख़िर में उस सीट से भी हाथ धो बैठी। राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव क्षेत्र सहारनपुर से शुरू होकर आगरा बेल्ट तक है और इस दल की सबसे ख़ास पहचान ये है कि इसमें जो नेता जिस जाति का होता है, वह हमेशा अपनी जाति बाहुल्यता वाले इलाके से लड़ना चाहता है।

महान दल- साल 2008 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर महान दल की स्थापना करने वाले केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश के मौर्य, भगत, भुजबल, सैनी और शाक्य जैसी कई जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले केशव देव मौर्य का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ

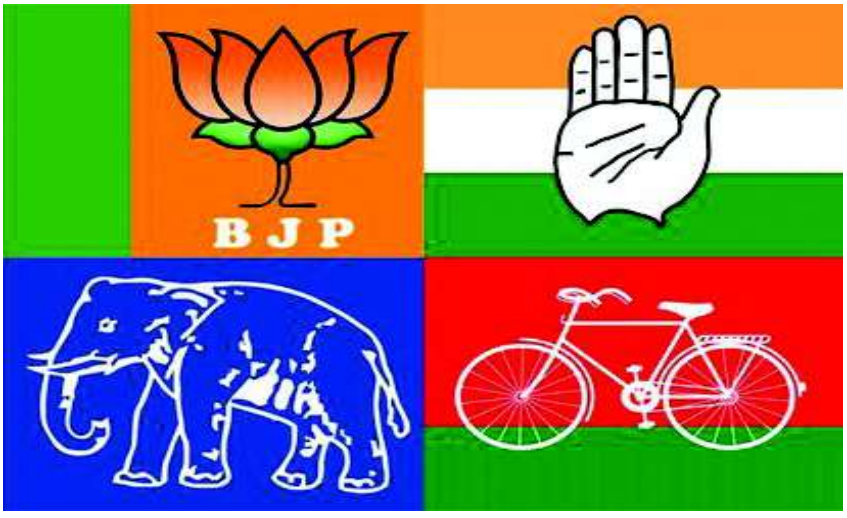

विधानसभाओं में अच्छा दखल माना जाता है। लेकिन केशव देव मौर्य उसी ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके नेता केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। यूपी में जिस समाज के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, उसी समाज के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य हैं।

निषाद पार्टी- प्रदेश के जातीय समीकरणों को समझने वाले मानेते हैं कि नदियों के किनारे बसने वाला ये समुदाय चुनावी गणित के लिहाज़ से काफ़ी ख़ास है। उत्तरप्रदेश में निषाद हर नदी के किनारे पर पाए जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यमुना से सटे ग़ाजियाबाद और नोएडा से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में ये समुदाय पाया जाता है। इसके बाद पूर्वांचल में गंगा के कछार क्षेत्र में इलाहाबाद से लेकर अन्य जगहों पर निषाद अच्छी ख़ासी संख्या में मौजूद हैं। हर जगह निषाद एक महत्वपूर्ण समुदाय है जो कि राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन निषाद हर दल के लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी लगातार इसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि, बीजेपी का इसमें पहले से ही काफ़ी आधार है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी की भी हिस्सेदारी है इस समुदाय में। यही नहीं, बीएसपी भी इस समुदाय से वोट हासिल करती है। बीजेपी की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के ज़रिए जो लाभार्थी बने हैं, अब उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश हो रही है।

अन्य छोटे दल- इन चार दलों के बाद उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव से लेकर पीस पार्टी समेत तमाम छोटी पार्टियां हैं। लेकिन छोटी पार्टियां बड़ी तब हो जाती हैं जब लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। ये दल अपने समाज की जनसंख्या के एक निश्चित फीसद का नेतृत्व करते हैं। और यह नेतृत्व बड़े दलों के लिए कभी वरदान तो कभी चुनौती बन जाता है।

हिमालय को हिला रही हैं जल विद्युत परियोजनाएं

प्रमोद भार्गव

उत्तराखंड में जोशीमठ जैसा खतरा हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मंडी जिले में तीन ग्रामों के घरों में जोशीमठ के घरों जैसी दरारें दिखने लगी हैं। पूरा हिमालय इस समय विकास एवं पर्यटन के लिए निर्मित की जा रहीं जल विद्युत परियोजनाओं का अभिशाप झेल रहा है। इन परियोजनाओं के लिए बनाए जा रहे बांधों पर ऊंगलियां शुरू से ही उठाई जाती रही हैं। टिहरी पर बंधे बांध को रोकने के लिए तो लंबा अभियान चला था। पर्यावरणविद और भू-वैज्ञानिक भी हिदायतें देते रहे हैं कि गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल धारा बाधित हुई तो गंगा तो प्रदुशित होगी ही, हिमालय का भी पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा सकता है? केदारनाथ में हुआ हादसा इसी पारिस्थितिकी तंत्र के गड़बड़ाने का दुष्परिणाम था। इस हादसे के सात साल बाद 2021 में उत्तराखंड में एक बार फिर तबाही का अलाम देखने में आया था। बर्फ के एक बड़े शिलाखंड के टूटने से आई बाढ़ के कारण चमोली जिले में ऋशिगंगा और धौलीगंगा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बनाए जा रहे बांध टूट गए थे। नतीजतन करीब 150 लोगों के बहने के साथ इतने ही लोगों की मौत की खबर आई थी। इस घटना ने भी आधुनिक विकास बनाम प्रलय की चेतावनी दी थी। लेकिन न

भारत सरकार चेती और न ही उत्तराखंड सरकार। अब जोशीमठ तो मानव निर्मित कृत्रिम आपदा का संकट झेल ही रहा है, लेकिन इसे यदि गंभीरता से नहीं लिया, तो धीरे-धीरे हिमालय की ज्यादातर आबादियां जोशीमठ की शक्ल में बदलती दिखाई देंगी।

औद्योगिक-प्रौद्योगिकी विकास के लिए हिमालय के पारिस्थितिकी तंत्र को इन्हें नजरअंदाज किया गया। सर्वोच्च न्यायालय भी इस बिंदु पर चिंता जता चुका है। केंद्र सरकार के अधीन जल संसाधन मंत्रालय 2016 में न्यायालय से कह चुका है कि अब यहां यदि कोई नई विद्युत परियोजना बनती है तो पर्यावरण के लिए खतरा साबित होगी। दरअसल 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी के बाद एक याचिका की सुनवाई करते हुए चैबीस निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला आज भी विचाराधीन है। बावजूद उत्तराखंड में बिजली के लिए जल के दोहन का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही रेल परियोजनाओं के लिए भी हिमालय के गर्भ में सुरंगे खोदी जा रही हैं और सतह पर आधुनिक सुविधा युक्त रेलवे स्टेषन बनाए जा रहे हैं। मसलन त्रासदियों से सबक लेने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देरही है। जबकि 1976 में गढ़वाल के आयुक्त महेषचंद्र मिश्रा की समिति ने 47 साल पहले ही कह दिया था कि जोषीमठ का जिस अनियमित ढंग से विकास हो रहा है, उससे यह कभी भी दरक सकता है। क्योंकि यहां नए निर्माण के लिए पहाड़ों को ताकतवर विस्फोटों के जरिए ढहाया जा रहा था। जिसने हिमालय की जडें हिलाने की शुरूआत कर दी थी।

दरअसल उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर एक लाख तीस हजार करोड़ की जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जिस ऋशिगंगा परियोजना पर 2021 में हादसा हुआ था, उसका कार्य

केंद्र सरकार के अधीन जल संसाधन मंत्रालय 2016 में न्यायालय से कह चुका है कि अब यहां यदि कोई नई विद्युत परियोजना बनती है तो पर्यावरण के लिए खतरा साबित होगी।

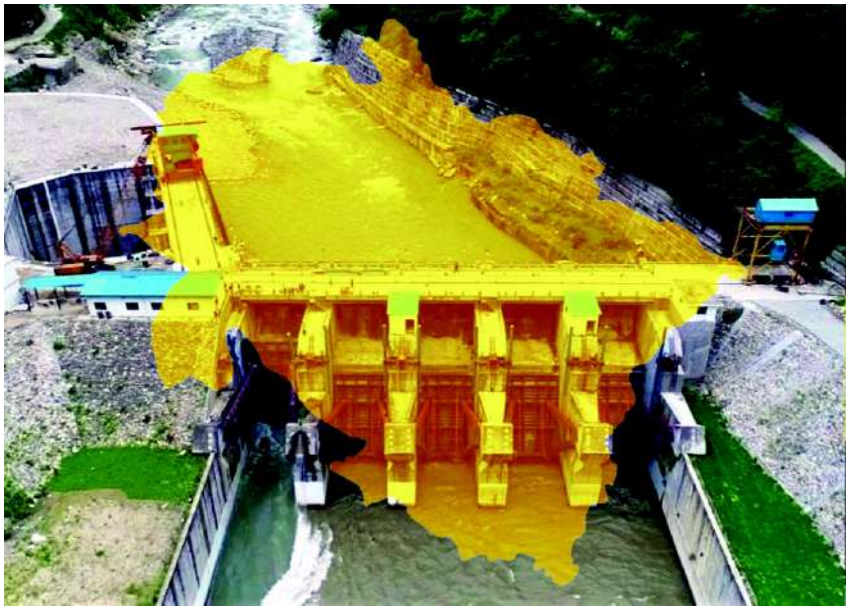

95 प्रतिशत पूरा हो चुका था। लेकिन इस हादसे ने डेढ़ सौ लोगों के प्राण तो लीले ही संयंत्र को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। इन संयंत्रों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों को काटने के बाद पहाड़ों को निर्ममता से छलनी किया जाता है और नदियों पर बांध निर्माण के लिए बुनियाद हेतु गहरे गड्ढे खोदकर खंबे व दीवारें खड़े किए जाते हैं। इन गड्ढों की खुदाई में ड्रिल मषीनों से जो कंपन होता है, वह पहाड़ की परतों की दरारों को खाली कर देता है और पेड़ों की जड़ों से जो पहाड़ गुंथे होते हैं उनकी पकड़ भी इस कंपन से ढीली पड़ जाती है। नतीजतन पहाड़ों के ढहने और हिमखंडो के टूटने की घटनाएं नंदादेवी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही हैं। इसीलिए ऋशिगंगा, धौलीगंगा, विष्णुगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी गंगा के जल अधिग्रहण क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं नदियों का पानी गोमुख से निकलकर गंगा की धारा को निरंतर बनाए रखता है। स्पश्ट है। गंगा की धारा को उद्गम स्थलों को ही ये संयंत्र अवरुद्ध कर रहे हैं। नतीजतन पहाड़ घंसकने के संकेत अब जोषीमठ के घरों में आई दरारों से स्पष्ट देखने में आने लगे हैं। यह हाल फिलहाल भले ही जोषीमठ में दिख रहा हो, लेकिन इसका कालांतर में विस्तार पूरे चामोली जिले में दिखाई देगा। फिलहाल जोशीमठ की 25 हजार की आबादी को नई जगह बसाने का सिलसिला सरकार ने शुरू जरूर कर दिया है, लेकिन देश में विस्थापन कभी भी उचित नहीं हुआ। विस्थापित लोगों को आजीवन दरिद्रता का दंश झेलने को मजबूर हो जाना पड़ता है।

ऋशिगंगा पर बन रहा संयंत्र रन ऑफ रिवर पद्धति पर आधारित था। अर्थात यहां

बिजली बनाने के लिए बांध तो नहीं बनाया गया था, लेकिन परियोजना को निर्मित करने के लिए नदी की धारा में मजबूत आधार स्तंभ बनाए गए थे। इन पर टावर खड़े करके विद्युत निर्माण के यंत्र स्थापित कर दिए गए थे। ऐसे में यह समूची परियोजना हिमखंड के टूटने से जो पानी का तेज प्रवाह हुआ, उससे क्षतिग्रस्त हो गई। यह संयंत्र जिस जगह बन रहा था, वहां दोनों किनारों पर संकरी घटियां हैं, इस कारण पानी का वेग अधिक था, जिसे आधार स्तंभ झेल नहीं पाए और संयंत्र बर्बाद हो गया। यह पानी आगे चलकर विष्णुगंगा तपोवन परियोजना तक पहुंचा तो वहां पहले से ही बने बांध में पानी भरा था, नतीजतन बांध की क्षमता से अधिक पानी हो गया और बांध टूट गया। यही पानी तबाही मचाता हुए निचले क्षेत्रों की तरफ बढ़ता चला गया। चूंकि हिमखंड दिन में टूटा था, इसलिए जन व धन की हानि ज्यादा नहीं हो पाई थी, अन्यथा बर्बादी का मंजर देखना मुश्किल हो जाता।

गंगा की इस अविरल धारा पर उमा भारती ने तब चिंता की थी, जब केंद्र में संप्रग की सरकार थी और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उत्तराखंड के श्रीनगर में जल विद्युत परियोजना के चलते धारादेवी का मंदिर डूब में आ रहा था। इस डूबती देवी को बचाने के लिए उमा धरने पर बैठ गई थीं। अंत में सात करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान करके, मंदिर को स्थांनातरित कर सुरक्षित कर लिया गया

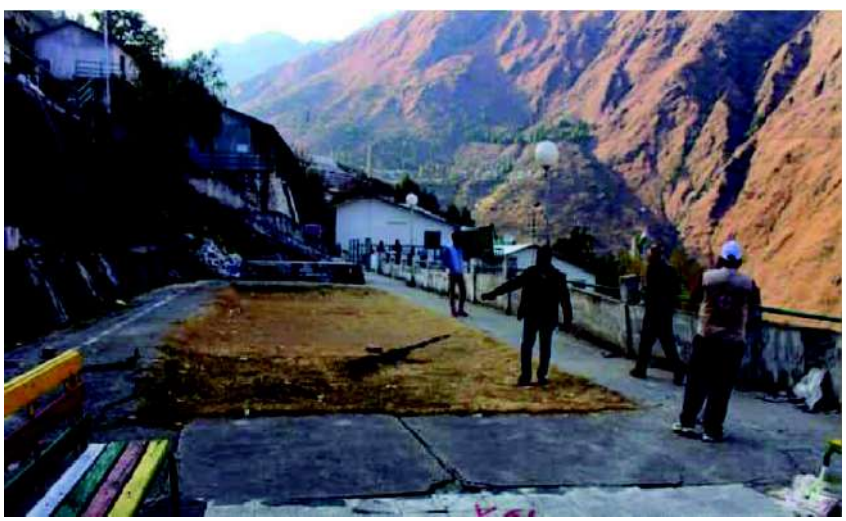

था। उमा भारती ने चैबीस ऊर्जा संयंत्रों पर रोक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान 2016 में जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जल संसाधन मंत्री रहते हुए केंद्र सरकार की इच्छा के विपरीत शपथ-पत्र के जरिए यह कहने की हिम्मत दिखाई थी कि उत्तराखंड में अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा नदियों पर जो भी बांध एवं जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, वे नदियों समेत गांव एवं कस्बों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती हैं? लेकिन इस इबारत के विरुद्ध पर्यावरण और ऊर्जा मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि बांधों का बनाया जाना खतरनाक नहीं है। इस कथन का आधार 1916 में हुए समझौते को बनाया गया था। इसमें कहा गया है कि नदियों में यदि एक हजार क्यूसेक पानी का बहाव बनाए रखा जाए तो बांध बनाए जा सकते हैं। किंतु इस हलफनामे को प्रस्तुत करते हुए यह ध्यान नहीं रखा गया कि सौ साल पहले इस समझौते में समतल क्षेत्रों में बांध बनाए जाने की परिकल्पनाएं अंतर्निहित थीं। उस समय हिमालय क्षेत्र में बांध बनाने की कल्पना किसी ने भी नहीं की थी?

इन शपथ-पत्रों को देते समय 70 नए ऊर्जा संयंत्रों को बनाए जाने की तैयारी चल रही थी। दरअसल परतंत्र भारत में जब अंग्रेजों ने गंगा किनारे उद्योग लगाने और गंगा पर बांध व पुलों के निर्माण की षुरूआत की तब पंडित मदनमोहन मालवीय ने गंगा की जलधार अविरल बहती रहे, इसकी चिंता करते हुए 1916 में फिरंगी हुकूमत को यह अनुबंध करने के लिए बाध्य किया था कि गंगा में हर वक्त हर क्षेत्र में 1000 क्यूसेक पानी अनिवार्य रूप से निरंतर बहता रहे। लेकिन पिछले एक-डेढ़ दशक के भीतर टिहरी जैसे सैकड़ों छोटे-बड़े बांध और बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए आधार स्तंभ बनाकर गंगा और उसकी सहायक नदियों की धाराएं कई

सुषमा स्वराज ने संसद में हिमालय पर निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि, विकास बनाम विनाश का सिलसिला उत्तराखंड में चल रहा है।

जगह अवरुद्ध कर दी गईं हैं।

2013 में हुए केदारनाथ हादसे के समय भाजपा नेत्री और सांसद सुषमा स्वराज ने संसद में हिमालय पर निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं पर कड़ा विरोध प्रकट करते हुए कहा था कि, विकास बनाम विनाश का सिलसिला उत्तराखंड में चल रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। नदियों पर बांध बनाकर, उन्हें अवरुद्ध किया जा रहा है। आखिर हम यह विकास अरबों-खरबों रुपए खर्च करके किसके लिए कर रहे हैं? प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और सब कुछ तबाह कर जाती है। धारादेवी को उत्तराखंड का रक्षक माना जाता है। लेकिन इसके ऊपर भी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन हैं। उमा भारती ने इस परियोजना का विरोध किया। दरअसल यहां एक बड़ी षिला को ही धारादेवी कहा जाता है, मूर्ति तो प्रतीक है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और निर्माण जारी रहा। यह मात्र संयोग नहीं है कि 16 जून 2013 को धारा देवी जलमग्न होती है और उसी दिन केदारनाथ में जल-प्रलय आता है, जो हजारों लोगों की जिंदगियां लील गया। लेकिन विडंबना देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं और उमा भारती को जल संसाधन मंत्री का प्रभार दिया जाता है। लेकिन स्थिति वही बनी रहती है, जो मनमोहन सिंह की सरकार में थी। इस कालखंड में विदेश मंत्री रहते हुए भी सुषमा स्वराज इस पूरे मुद्दे पर पूरे पांच साल मौन रहती हैं। बहरहाल हिमालय की नदियों को सुरंगों में डालकर उनके दोहन का सिलसिला और तेज हो जाता है। इसी का परिणाम 2021 की त्रासदी थी और इसी का विस्तार हम जोशीमठ में देख रहे हैं।

चीन को लेकर सावधानी जरूरी

भारतीय सेना के जवानों ने तबांग में चीनी घुसपैठ के प्रवास को साहसपूर्वक न केवल विफल कर दिया बल्कि अपने शक्ति शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। जिससे भारतीय सेना का आम जन में गौरव भी बढ़ा है और देशवासियों में आत्मविश्वास का संचार भी हुआ है।

रघु ठाकुर

भारत-चीन की सीमा पर पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ रहा है, और विशेषतः तबांग की घटना के बाद कुछ ज्यादा ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना के जवानों ने तबांग में चीनी घुसपैठ के प्रवास को साहसपूर्वक न केवल विफल कर दिया बल्कि अपने शक्ति शौर्य का जबरदस्त प्रदर्शन भी किया। जिससे भारतीय सेना का आम जन में गौरव भी बढ़ा है और देशवासियों में आत्मविश्वास का संचार भी हुआ है।

फिर भी अभी राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टिकोण से कुछ चिंतायें आमजन के मस्तिष्क में हैं। मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसे समाचार आये हैं कि चीनी सैनिक निरंतर घुसपैठ करने के प्रयास में लगे हुए है। पिछले वर्ष भारत की सीमा में जो सैनिक घुसकर आये थे और जिन्होंने लगभग दो सौ से ढाई सौ वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया था, वहाँ से चीनी

सैनिकों को भारत अभी तक हटा नही सका है। चीनी और भारतीय सैनिक अधिकारियों के बीच निरंतर बैठके हुई हैं, उनमें यह समझौता भी किया गया कि भविष्य में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच अपनी-अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अगर कोई मतभेद या विवाद होता है तो किसी भी पक्ष से आग्नेय आस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। यानि केवल शारीरिक बल से एक दूसरे को रोकने का प्रयास किया जायेगा। यह समझौता युद्ध रोकने की दृष्टिकोण से तो उपयोगी हो सकता है, परन्तु भारतीय सीमाओं की दृष्टिकोण से या पुरानी कब्जाई हुई जमीन वापिस लेने के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है।

वर्ष 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया था और भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था जो कि अभी भी चीन के कब्जे में है तथा वह जमीन वापिस नहीं ली जा सकी। लगभग 23 वर्षो तक चीन और भारत के बीच रिश्ते कूटनीतिक सहित टूटे रहे। यद्यपि चीन व भारत ने अपने-अपने दूतावास बंद नहीं किये थे। परन्तु संबंधों में एक तीखा अवरोध पैदा हो गया था। यह कटु सत्य है कि वर्ष 1978 में लगभग 16 वर्षो के बाद पहली बार भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी चीन गये थे। हालांकि तब भी चीन ने भारत सरकार को अपने मनसूबे स्पष्ट कर दिये थे न केवल शब्दों के द्वारा बल्कि कर्म के द्वारा। जब स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन में थे तभी चीन ने वियतनाम पर हमला बोल दिया। जिसकी प्रतिक्रिया अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर बहुत तीखी हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. मोरारजी देसाई ने उन्हें रात को ही वापस लौटने को कहा। उसके 8 वर्ष बाद 1985-86 में और अगर 1962 से देखें तो लगभग 24 वर्षो के बाद चीन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री स्व. राजीव गाँधी थे। इस हृदय परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं, यह शोध का विषय है? संभव है कि अमेरिका की चीन के प्रति बदलती हुई नीति ने इन दौरों को प्रोत्साहित किया हो? क्योंकि अमेरिका अपनी विदेश नीति को दशकों पूर्व तय करता है और उस दिशा में दुनिया का दिमाग बनाता है, इस संदेह का एक कारण यह भी है कि सन् 1985 में स्वर्गीय राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कई ऐसे निर्णय हुये हैं जो भारत के लिये या भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत उचित नही कहे जा सकते। स्वर्गीय राजीव गाँधी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का अमेरिका के प्रति समान सोच भी एक कारण हो सकता है।

सन् 1991 में स्व. नरसि हा राव के

प्रधानमंत्री बनने के बाद और अंर्तराष्ट्रीय पूंजीवाद के दस्तावेज़ विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति को लगभग उल्टा खड़ा कर दिया। भारत ने 1991 के बाद लुक टू द ईस्ट विदेश नीति का निर्धारण किया और पश्चिम के बदले मुख्यतः चीन वर्मा, बांगलादेश, नेपाल और आदि को विदेश नीति का लक्ष्य बनाया। भारत की विदेश नीति का यह परिवर्तन भी एक प्रकार से अमेरिका का पिछलग्गूपन था। अमेरिका ने चीन के साथ टूटे हुए व्यापार के बंधनों को पुनः शुरू किया तथा चीन को अपना बाजार खोला। और चीन ने अपना बाजार अमेरिका को खोला। वैश्विक स्तर पर एक नया जुमला शुरू हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तें और विदेश नीति के लिए व्यापार ही मजबूत बना सकता है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि चीन आर्थिक रूप से भारी समृद्ध हुआ। दुनिया के बाजारों पर चीन ने अपने सस्ते सामान को फैला दिया। चूंकि चीन में सा यवादी शासन है जो एक अर्थ में निरंकुश या तानाशाही शासन है, के कारण श्रम लागत सस्ती रहती है।

मार्क्सवादी भले ही दुनिया में नारा लगाते हों कि दुनिया के मजदूर एक हो - पूँजीवाद मुर्दाबाद, परन्तु चीनी व्यवस्था में ये नारें संभव नहीं है और ना कोई मजदूर आन्दोलन बचा है। वहां तो सत्ता के विरोध का मतलब राष्ट्रद्रोह और मृत्यु दण्ड है। इसलिए चीन सस्ता सामान बनानें में सफल हुआ और उसके सस्ते सामान ने ना केवल अमेरिका के बल्कि दुनिया के बड़े भू-भाग पर कब्जा जमा लिया। तथा चीन की आर्थिक स पन्नता ने चीन को अपनी पूँजी और प्रभाव को फैलाने का अवसर दिया। चीन ने भी एक प्रकार से वैश्विक साहूकारी शुरू कर दी तथा श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल बांगलादेश और दुनिया के अनेक देशों को आर्थिक सैन्य व कूटनीतिक मदद तथा कर्ज देकर अपने प्रभाव में लिया। नेपाल में हाल ही में ओली के समर्थन से प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के पीछे स्पष्टतः चीन की भूमिका है जबकि ओली व प्रचंड एक दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़े थे। चीन की आर्थिक क्षमता इतनी बढ़ी है कि अमेरिका को अमेरिका के भीतर भी वह टक्कर और आर्थिक मदद देने लगा। और दुनिया में पैसे व सैन्य शक्ति के आधार पर जो प्रभाव व दबाव पहले अमेरिका का था काफी हद तक उसे चीन ने अपने प्रभाव में ले लिया। यूरोप के बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए चीन ने वन बेल्ट वन रोड की योजना शुरू की और चीन से लेकर ईरान तक एक सड़क मार्ग बनाकर अपने बाजार को पहुंचाने की योजना तैयार की। इस योजना पर चीन काफी आगे बढ़ा भी है परन्तु भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं ने इस बाबत कोई ठोस चिंतन नहीं किया तथा पश्चिम को लगभग उपेक्षित कर दिया।

परिणामतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक चीन की घुसपैठ गहरी हो गयी। इस व्यापारिक सिद्धांत के तहत भारत ने अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की वापिसी व सुरक्षा पर ध्यान देना कम कर दिया। भारत के नीति निर्माताओं की सोच थी कि चीन अपने व्यापारिक, आर्थिक हितों के लिए अब आगे घुसपैठ नहीं करेगा। तथा भारत के कारपोरेट पोषित राजनेताओं ने दो नये शब्दों को कहना और फैलाना शुरू कर दिया। पहला शब्द था एल.ओ.सी. और इसके बाद दूसरा शब्द गढ़ा गया एल.ए.सी.।

नब्बे के दशक के पहले से ही भारत-चीन के सीमा विवाद को हल करने के लिए एक सत्ता पोषित बौद्धिक धड़ा कहने लगा था कि भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा अंग्रेजों ने खींची थी जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है वह छोड़ देना चाहिए और जो भूमि जिसके नियंत्रण में है वहां तक उसके अधिकार को मान लेना चाहिए। याने भारत की जो लगभग 30-40 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि चीन ने 1962 से कब्जाई है उसे चीन का मान लेना चाहिए। यह एक प्रकार से समझौते के नाम पर या व्यापार के नाम पर सीधा भारतीय भूमि का समर्पण था। यहाँ यह बता दूँ कि डॉ. राम मनोहर लोहिया तो मैकमोहन लाइन को भी अंग्रेजों के द्वारा खींची गयी गलत रेखा मानते थे तथा इसे वास्तविक सीमा नहीं मानते थे। बल्कि वे कहते थे कि, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तो मैकमोहन लाईन के आगे तक है जिसमें स पूर्ण हिमालय और उसके आगे तक की मानसरोवर सहित भारतीय भूमि है। इतिहास में इसके प्रमाण है। परन्तु भारतीय सत्ताधीशों ने भारत की प्राचीन विभाजन रेखा को तो भुला ही दिया यहां तक की 300 तीन सौ साल के बाद अंग्रेजों के द्वारा उनकी सुविधा के लिए खींची गयी मैकमोहन लाइन को भी भुला दिया। और लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम पर भारत की 1962 में कब्जाई जमीन को भी इस जुमले से चीनी स्वीकार करने की मनोस्थिति बनाना शुरू कर दिया। परन्तु चीन की विस्तारवादी और साम्रायवादी नीति रूकने वाली नहीं है। चीन ने भारत की लगभग कोई तीन हजार वर्ग किलोमीटर जमीन को 1962 के बाद कब्जा लिया परंतु व्यापार करने वालों के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय सीमा से कोई लेना देना नहीं है। तथा अब वे लाइन ऑफ एक्चुवल कंट्रोल की बात करने लगे हैं। एल.ओ.सी. अपने आप में एक गलत शब्द था और एल.ए.सी. की चर्चा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और भी खतरनाक है। उसका मतलब है कि ताकत के आगे झुकना और सीमाओं को देते जाना। कल मान लो कि कोई भारत की सीमाओं का फिर अतिमण करें तथा बलात कब्जा करें तो एल.ए.सी. का मतलब होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम पर उसे भी छोड़ देना। यह एक नया शक्ति साम्रायवाद का सिद्धांत होगा जो ताकतवर देशों के द्वारा कमजोर देशों को निगलता चला जायेगा। क्या हम शक्ति साम्रायवाद के इस नये अजगर को स्वीकार करेंगे? मेरी राय में किसी भी भारतवासी और राष्ट्र प्रेमी को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए बल्कि कहना चाहिए कि हम ना एल.ओ.सी. मानेंगे न एल.ए.सी. मानेंगे और यहां तक की अंग्रेजों की खींची मैकमोहन लाइन को भी अस्वीकार कर भारत की प्राचीन भूमि सीमा को भारत की सीमा मानेंगे।

परन्तु आज बाजार की आर्थिक शक्तियों को मुनाफा कमाना व उनसे जन्मी राजसत्ताओं का उद्देश्य तो केवल सश्रा पाना है। उनका कोई धर्म ईमान या राष्ट्रवाद नहीं है, उनका तो एक मकसद है कि बाजार के माध्यम से रूपया कमाना है। पिछले दिनों कितना प्रचार किया गया कि भारत सरकार ने कई प्रतिबंध चीन पर लगायें है। उनके ऐप बंद किये हैं आदि-आदि। भारत के व्यापारिक संगठनों ने जोर शोर से चीनी माल के बहिष्कार के विज्ञापन छपवाये पर वस्तु स्थिति यह है कि भारत का चीन से आयात बढ़ रहा है तथा लगभग 3 गुना बढ़कर साढ़े नौ लाख करोड़ रूपये का हो गया है। मतलब साफ है कि बहिष्कार के नारे केवल धोखे के लिए है। राष्ट्रवाद की चर्चाएं केवल गुमराह करने के लिए हैं असलियत तो केवल पैसा कमाना है। देश को सावधान होना चाहिए वरना तिजोरियां भरती जायेंगी सत्ताधीश बने रहेंगे पर देश की सीमायें सिकुड़ती जायेंगी।

Pollution Control in United States

Shaifali Dubey/Anjana Mishra

There is general agreement that we must control pollution of air, water and land, but there is considerable dispute over how controls should be designed and how much control is enough. The pollution control mechanisms adopted in the United States have tended toward detailed regulation of technology, leaving polluters with little choice in how to achieve the environmental goals. This "command-and-control" strategy needlessly increases the cost of pollution controls and may even slow our progress toward a cleaner environment.

In 1970, popular concern about environmental degradation coalesced into a major political force, resulting in President Richard Nixon's creation of the federal Environmental Protection Agency (EPA) and the first of the major federal attempts to regulate pollution directly—the Clean Air Act Amendments of 1970. Since then, the federal role in regulating pollution has grown immensely, unleashing many regulatory responsibilities on the EPA and a cascade of regulations on local governments and the business community. Now, that has begun to change somewhat as environmentalists have increasingly realized that markets can work to allocate pollution reduction responsibilities efficiently among firms and across industries. Although the command-and-control approach is still the norm, environmental lobbyists and legislators have, on occasion, considered market-based approaches to pollution control. Most of the proposals for limiting Global warming for

example, explicitly include market-based approaches for controlling carbon dioxide emissions.

In virtually every anti-pollution law, Congress has instructed the EPA to establish and enforce specific pollution standards for individual polluters. The EPA generally bases these standards on some notion of the "best available" or "best achievable" technology for each source of pollution in each industry. Since, each pollutant has many sources, the EPA often sets literally hundreds of maximum-discharge standards for any single pollutant.

Existing pollution sources (such as old factories) are generally required to meet less onerous standards than those applicable for new sources, largely because it is considered more costly to retrofit an old factory than to build pollution control devices into a new one.

However, even the definition of "new" requires further regulations because the EPA must distinguish between, for example, when a utility simply repairs or refurbishes an "old" fossil-fuel-fired boiler and when it replaces enough components to make it a "new" boiler. Complicating matters further, standards for both existing and new sources are often stricter in regions with a higher-quality environment (i.e., cleaner air, cleaner water, etc.). Since, the tighter standards on new or upgraded sources may reduce the incentive to replace the dirty, older facilities, in 2003 the EPA revised its rules to allow power plants and other major polluting facilities to be modernized without triggering the full panoply of "new-source review" requirements if the modernization involved did not involve a major design change and did not cost more than 20 percent of a completely new facility.

The Cost of Pollution Controls

The way pollution controls are often built into the production process makes any estimation of their cost extremely difficult. In

addition, pollution controls often discourage new investment and production, but because the value of what is not produced is not seen, no one currently calculates such indirect costs. The federal government has, however, estimated a subset of costs—namely, direct expenditures on pollution controls. These expenditures cost governments and private entities an estimated $50 billion plus in 2002 alone. Some thirty-one billion dollars was spent on air-pollution abatement, seventeen billion on water-pollution controls, and eight billion for a variety of solid waste, hazardous waste, and other programs.

The most costly and complex federal pollution-control policy has been the motor vehicle emissions-control program. In order to enforce automobile standards set by Congress, the EPA must test each model line of new cars and must also test a random sample of vehicles already on the road. The EPA imposed the first federally mandated exhaust emission controls on new cars in 1967 and tightened these controls several times in the next twenty-five years. The Clean Air Act requires that emission controls on new cars work for at least the first eighty thousand miles driven or for eight years. The EPA estimated that the direct expenditures for compliance with the new-vehicle emissions standards totaled nineteen billion dollars in 2002.

Among the federally funded programs, two have been especially costly. The larger of these is the Municipal Sewage Treatment Construction Grant program begun in 1973. Through this program, the federal government directly underwrote grants totaling more than forty-three billion dollars by 1983 to pay for municipal sewage-treatment plants. Over time, the number of municipal sewage-treatment plants requiring major upgrades was reduced, and the federal contribution has now declined to less than two billion

dollars per year.

The second program is better known. In 1980, Congress established the Superfund to finance the cleaning of hazardous waste sites. This program required private entities responsible for hazardous dumps to clean them up, but if these parties could not be found, the cleanup would be funded by the government through general revenues and a tax on petroleum feed-stocks. In 1986, a new statute—the Superfund Amendments and Reauthorization Act—levied a federal tax on all corporations with taxable income over $2 million to help fund these remedial actions. Thus, corporations that had nothing to do with old hazardous waste sites or that do not even generate toxic waste were required to pay for the pollution others left behind. The Superfund program has been plagued with delays and a lack of detailed monitoring of its results. The EPA estimated its cost at $7.7 billion in 2002, but the EPA cannot estimate the program's benefits because it does not have the requisite evidence that the program has improved the ecosystem. Moreover, the EPA admits that it could not place a value on such improvements even if it had the requisite data.

The Economic Effects of Pollution Controls

Pollution controls divert economic resources from other economic activities, thereby reducing the potential size of measured national output. As long as the increase in the value of the environment is at least one dollar for each additional dollar spent on controls, the total value of goods, services, and environmental amenities is not reduced. Unfortunately, that seldom happens, for at least three reasons.

First, the Congress or the EPA may decide to control the wrong substances or to control some discharges too strictly. Congress's own Office of Technology Assessment concluded, for example, that attempting to reach the EPA's goal for urban smog reduction could cost more than $13 billion per year but result in less than $3.5 billion in improved health, agricultural, and amenity benefits. Attempting to use invariant national pollution standards to control smog, which

varies substantially across geographic regions and over the seasons of the year, continues to be a very inefficient policy.

Second, regulatory standards can result in very inefficient patterns of control. Some polluters may be forced to spend twenty-five thousand dollars per ton to control the discharge of a certain pollutant, while for others the cost is only five hundred dollars per ton. Obviously, shifting the burden away from the former polluter toward the latter would result in lower total control costs for society for any given level of pollution control.

Third, pollution controls can have deleterious effects on investment in two ways. First, by making certain goods—chemicals, paper, metals, motor vehicles—more expensive to produce in the United States, they raise the prices of these goods and thereby reduce the amount of each demanded. Second, because controls are generally more onerous for new sources than for older, existing ones, managers are more likely to keep an old plant in use rather than replace it with a new, more efficient facility, even though the new facility would produce the same goods as the old one.

The command-and-control approach is flawed in other ways, too. It does little to encourage compliance beyond what is mandated. Regulations are introduced only after noticeable damage has occurred, and they may be difficult to enforce. Polluters who manage to avoid legislative scrutiny continue to pollute.

Market-Based Approach to Pollution Control

Problems like these have led policymakers to look for more efficient means of cleaning up the environment. As a result, the 1990 Clean Air Act Amendments look very different from their predecessors of the 1970s because they include market-based incentives to reduce pollution.

Market incentives are generally of two forms: pollution fees and so-called marketable permits. Pollution fees are simply taxes on polluters that penalize them in proportion to the amount they discharge into an air-shed, waterway, or local landfill. Such taxes are common in Europe but have not been used in the United States. Marketable permits are essentially transferable discharge licenses that polluters can buy and sell to meet the control levels set by regulatory authorities. These permits have been used in the United States because they do not impose large taxes on a small set of polluting industries, as would be the case with pollution fees.

The 1990 Clean Air Act allows the EPA to grant "emissions permits" for certain pollutants. These are, in effect, rights to pollute that can be traded among polluters. Imagine a giant bubble that encloses all existing sources of air pollution. Within that bubble, some emitters may pollute more than the control level as long as other polluters compensate by polluting less. The government or some other state or regional authority decides on the desired level of pollution and the initial distribution of pollution rights within an industry or for a geographic region—the "bubble" that encloses these sources. Purchases and sales of permits within the "bubble" should reduce the total level of pollution

to the allowable limit at the lowest total cost.

For example, a St. Louis study found that the cost of reducing particulate emissions for a paper products factory was $4 per ton, while the cost to a brewery was $600 per ton. The Clean Air Act could require St. Louis to reduce its emissions by a certain amount. Under the traditional approach, the brewery and the paper factory would each be required to cut emissions by, say, ten tons. The cost to the paper factory would be only $40, while the cost to the brewery would be $6,000. But with tradable permits, the brewery could pay the paper factory to cut emissions by twenty tons so that the brewery could continue to operate without reducing emissions at all. The net result is the same emission reduction of twenty tons as under the command-and-control approach, but the total cost to society of the reduction is only $80 instead of $6,040.

The tradable permits work. The most notable success has been in reducing sulfur dioxide emissions from electric utility plants. The 1990 Clean Air Act Amendments contained a provision that set a cap on total sulfur dioxide emissions that would decline over time to about half their 1980 level. Instead of requiring all power plants to meet a technology-based standard, electric utilities were allocated a share of the maximum allowable national emissions. They could then buy or sell emission allowances, depending on their needs and their marginal costs of abatement. The program has worked spectacularly well, reducing total control costs by an estimated $750 million to $1.5 billion per year relative to the cost of the former technology-based standards, while meeting or exceeding the environmental goals of sulfur dioxide reductions.

Marketable permits also were used to phase down the use of chlorofluorocarbons (CFCs) in order to preserve the stratospheric ozone layer and to phase out the use of lead in gasoline in the 1980s. The CFC policy was instituted in 1990 and succeeded in mitigating the opposition to a phase-down of CFCs in developed countries, particularly the United States. The lead phase-down was designed to allow smaller refineries to acquire marketable permits rather than employing technologies that the larger refineries could implement more efficiently. This program saved hundreds of millions of dollars per year, promoted technological progress, and allowed a more orderly transition of refinery capacity without sacrificing environmental quality. Protecting our environment does not have to put an end to economic progress. Free markets in permits to pollute, like free markets for other resources, can ensure that pollution is controlled at the lowest cost possible.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.